घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 287- बुधवार 19- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगा हाई पावर्ड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी,सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक हाई पावर्ड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। यह कमेटी 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक छात्रों के मार्च के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की भी पड़ताल करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्टियों से उन पूर्व जजों, पूर्व डीजीपी या रिटायर्ड सीबीआई डायरेक्टरों के बारे में सुझाव मांगे, जिन्हें उस पैनल में शामिल किया जा सके जो इस बात की जांच करेगा कि क्या नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में गड़बडियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और बिहार में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और सिर्फ इसलिए 'लाठीचार्ज' को सही नहीं ठहराया जा सकता कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी (तथ्यों की जांच करने वाली समिति) से समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है ताकि बेंच जरूरी निर्देश दे सके, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीडन और ऑनलाइन उत्पीडन के मामलों को देखते हुए।

अर्जुन अवॉर्ड की लिस्ट जारी..दिव्या-तेजस्विन-गायत्री समेत 17 खिलाड़ियों को मिली खुशखबरी

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश के अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों,कोचों और संस्थाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए एथलेटिक्स स्टार तेजस्विन शंकर,शतरंज खिलाड़ी विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख के अलावा बैडमिंटन की जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली समेत कई नाम शामिल हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स हर साल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों के लिए नामों को मंजूरी दी गई है। अर्जुन अवॉर्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के साथ नेतृत्व क्षमता,खेल भावना और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए कुल 17 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इनमें एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर,मुहम्मद अजमल वरियाथोडी और प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं। बैडमिंटन से ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चुना गया है। बॉक्सिंग में नरेंद्र और शतरंज में विदित संतोष गुजराती तथा दिव्या जितेंद्र देशमुख को सम्मान मिलेगा। डेफ शूटिंग से धनुष श्रीकांत, हॉकी से लालरेम्सियामी और राजकुमार पाल भी पुरस्कार सूची में हैं।

देश में बनेंगे फाइटर जेट-टैंक और मिसाइल सिस्टम के उपकरण...सरकार ने 405 प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की; 3000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सरकार हथियारों-मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 405 स्ट्रैटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की। इनमें अलग-अलग मशीनों के हिस्से,स्पेयर पार्ट्स,कंपोनेंट,सब-सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल है। हेलिकॉप्टर और लड़ाकू विमान से जुड़े सामान,टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के सामान,रडार,सोनार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टैंक रोधी गोला-बारूद भी शामिल हैं। अगर ये सामान देश की कंपनियां ही बनाती हैं तो कुल 3,070 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इसका मकसद डिफेंस सेक्टर में आयात घटाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ानाा है। रक्षा मंत्रालय के तहत जारी लिस्ट में हर प्रोडक्ट के भारतीयकरण के लिए तय समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज

मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी...

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाम बताया गया था। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे चार वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा था...कम दर्द देने वाले तरीके अपनाए जाएं : वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, जबकि गोली मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगने का दावा किया गया। याचिका में सीआरपीसी की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इसी धारा के तहत मौत की सजा पाए दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाता है, जब तक उसकी मौत न हो जाए। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और गरिमा के अधिकार के खिलाफ बताया गया। मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को फांसी और जहरीले इंजेक्शन में से कोई एक तरीका चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट बोला....केंद्र चाहे तो फांसी के तरीके की समीक्षा करा सकता है...

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक,मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दोषी की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है।

देवेंद्र महतो बोले...अभी मिली पहली जीत व्यापक सुधार का आंदोलन जारी रहेगा

रांची,18 अगस्त 2026। झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित 14 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले को आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द होना संघर्ष का अंतिम पड़ाव नहीं है और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोप सामने आए थे, उन्हें रद्द किया जाना छात्रों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल किसी एक परीक्षा को रद्द कराना नहीं, बल्कि झारखंड की पूरी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को ऐसी व्यवस्था की गारंटी देनी होगी, जिसमें भविष्य में पेपर लीक, प्रश्नपत्र की सेटिंग या परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश न रहे। इसके लिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के हर चरण का ऑडिट होना चाहिए और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी से लेकर संबंधित अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महतो ने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने लंबा संघर्ष किया है

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल...विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी नियुक्त सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के चुनावों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे में चुनाव की कमान तावड़े को सौंपे जाने को अहम माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया को दी गई है। पंजाब में बीजेपी के सामने संगठन को मजबूत करने और अपने चुनावी आधार का विस्तार करने की चुनौती है। वहीं, राज्यसभा सांसद तरुण चुग को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुग पहले भी पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं, पूर्व आरएसएस नेता राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पार्टी ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष को उनके पद पर बरकरार रखा है। मीडिया की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास ही रहेगी, जबकि सोशल मीडिया की कमान छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को सौंपी गई है। बीजेपी के इस संगठनात्मक फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनावों पर पार्टी का खास फोकस साफ नजर आ रहा है। यूपी, पंजाब और गुजरात में अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को और धार देने का संकेत दिया है।

पीएम केयर्स फंड में घरेलू डोनेशन 30% घटा

479 करोड़ रहा,पिछले साल विदेशी दान में भी कमी आई,फंड में अभी 8452 करोड़

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घटकर करीब 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान में भी कमी आई। यह 18% घटकर 92.8 लाख रुपए रह गया है। 2023 में घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपए था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में फंड में टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए थी। 2025 में यह 8,452 करोड़ रुपए हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद पीएम केयर्स फंड बनाया था। प्रधानमंत्री ही इस फंड के अध्यक्ष होते हैं। इस फंड में पूरी राशि दान के रूप में आती है और इसे सरकार के बजट से कोई पैसा नहीं मिलता।

पीएम केयर्स में फॉरेन फंडिंग घटी : इस फंड में फॉरेन फंडिंग 2020-21 में 495 करोड़ रुपए थी, जो अगले दो वित्त वर्षों में घटकर 40 करोड़ रुपए और 2.57 करोड़ रुपए रह गई। 2023-24 में विदेशी दान से 1.13 करोड़ रुपए मिले थे। 2024-25 में विदेशी योगदान 92.8 लाख रुपए रहा। यह 2019-20 में मिले 39.7 लाख रुपए के बाद यह सबसे कम डोनेशन रहा। 2023 में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर पिछले साल 15.37 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024 में यह रकम 15.6 करोड़ रुपए थी। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल समय-समय पर इमरजेंसी केयर बढ़ाने के लिए किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और वेंटिलेटर खरीदने पर पैसा खर्च किया गया। 2021-22 में प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट पर 1,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेंटिलेटर पर 835 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में फंड का कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपए था।

रक्षा मंत्रालय ने छठी स्वदेशीकरण सूची में 405 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2026। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करके 405 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सूची में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स,सब-सिस्टम,सब-असेंबली, स्पेयर पार्ट्स,कंपोनेंट्स और कच्चा माल शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं को अब अलग-अलग समय सीमा में स्वदेशी स्रोतों से ही खरीदा जाएगा। इनमें भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की 16 वस्तुएं और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की 389 वस्तुएं हैं।

28 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर केस रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले...

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अदालत को बताया कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके खिलाफ कुल 89 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। अदालत के सामने पेश की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19-19 मामले हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के खिलाफ 18 मामले दर्ज बताए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पांच, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चार-चार मामले लंबित हैं। रिपोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ दो-दो आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल...कई जिलों के कलेक्टर बदले

कांकेर,मुंगेली,सक्ती,गरियाबंद,कबीरधाम और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर बदले; सरगुजा जिला पंचायत की कमान रोमा श्रीवास्तव को...

रायपुर,18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय,नगरीय प्रशासन, खाद्य, जल जीवन मिशन,पर्यटन,समाज कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कांकेर से लेकर कबीरधाम तक बदले कलेक्टर

कांकेर कलेक्टर नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास बनाया गया है। उनकी जगह कुंदन कुमार को कांकेर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार के स्थान पर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो को मुंगेली भेजा गया है। सक्ती कलेक्टर की जिम्मेदारी अब जयश्री जैन संभालेंगी। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को कबीरधाम कलेक्टर बनाया गया है। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

गरियाबंद कलेक्टर बदले,रणबीर शर्मा को कमान

गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके को संयुक्त सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर संचालक समाज कल्याण रणबीर शर्मा को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के नए कलेक्टर के रूप में तनुजा सलाम की पदस्थापना की गई है। वे वर्तमान में संचालक, खेल एवं युवा कल्याण के पद पर थीं।

सरगुजा जिला पंचायत की नई सीईओ रोमा श्रीवास्तव

तबादला सूची में सरगुजा को भी महत्वपूर्ण बदलाव मिला है। रोमा श्रीवास्तव,भा.प्र.से. (2020), उप सचिव,मंत्रालय को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत सरगुजा पदस्थ किया गया है। वहीं नारायणपुर जिला पंचायत सीईओआकांक्षा शिक्षा खलखो को उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ करते हुए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी रिमिजियुस एक्का को...

नगरीय प्रशासन एवं विकास के संचालक रिमिजियुस एक्का को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पीएचई सचिव मो. कैसर अब्दुलहक जल जीवन मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

पर्यटन मंडल की कमान सौमिल रंजन चौबे को : कृषि विभाग के उप सचिव सौमिल रंजन चौबे को प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल बनाया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही पर्यटन मंडल के असंवर्गीय पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है।

विलास संदिपान को नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोसकर विलास संदिपान को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रबंध संचालक,नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस अतिरिक्त प्रभार के लिए सहमति प्रदान की है। वहीं पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग वन विभाग को वापस कर दी गई हैं।

दुर्ग निगम आयुक्त भी बदले...

लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक लीना कोसम को आयुक्त,नगर पालिक निगम दुर्ग पदस्थ किया गया है। वहीं अपर कलेक्टर नारायणपुर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भुवनेश यादव को आदिम जाति विकास,अनुसूचित जाति विकास,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार,जगदीश सोनकर को विशेष सचिव खाद्य विभाग तथा गजेन्द्र सिंह ठाकुर को संचालक समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी

आदेश के अनुसार किमारानी बोरा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से मुख्य सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं आर. संगीता को सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है।

एक नजर में प्रमुख बदलाव

- कांकेर कलेक्टर–कुंदन कुमार
- मुंगेली कलेक्टर–अमृत विकास तोपनो
- सक्ती कलेक्टर–जयश्री जैन
- गरियाबंद कलेक्टर–रणबीर शर्मा
- कबीरधाम कलेक्टर–तुलिका प्रजापति
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी कलेक्टर–तनुजा सलाम
- सीईओ जिला पंचायत सरगुजा–रोमा श्रीवास्तव
- आयुक्त नगर निगम दुर्ग–लीना कोसम
- अपर कलेक्टर बिलासपुर–बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई
- मिशन संचालक जल जीवन मिशन–रिमिजियुस एक्का
- प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल–सौमिल रंजन चौबे

संपादकीय

सुविधा की कीमत चुकाने का समय

अपने आसपास किसी सब्जी के ठेले,टी-स्टाल या दवाई की दुकान या किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर नजर डालिए तो बहुत संभव है कि आपको वहां यूपीआइ क्यूआर कोड नजर आए। केवल जुलाई 2026 में ही भारत में 29.9 लाख करोड़ रुपये के 2,366 करोड़ यूपीआइ लेनदेन हुए। भारत का बनाया हुआ यह एक ऐसा सिस्टम है,जिसे पूरी दुनिया सराहती है। चूंकि लगभग सभी लोग इसका उपयोग करते हैं,इसलिए जब अगस्त में संसद ने कुछ यूपीआई भुगतानों को शुल्क के दायरे में लाने संबंधी कानून को हरी झंडी दिखाई तो उस पर आक्रोश दिखा। लोगों को लगा कि उनसे मुफ्त सुविधा छीनी जा रही है। यह भाव बहुत ही स्वाभाविक है। इसके पीछे तमाम पहलू उत्तरदायी हैं।

कानून में जिस शुल्क का उल्लेख है वह मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर है, जिसका भुगतान उपभोक्ता नहीं,बल्कि व्यापारी को करना होगा। यह शुल्क 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान और बड़े कारोबारियों पर ही लागू होगा। किसी मित्र,परिचित या परिवार के सदस्य को होने वाला सामान्य भुगतान पहले की ही तरह शुल्क मुक्त रहेगा। छोटे दुकानदारों को भी भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क की 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत की प्रस्तावित दर भी बहुत कम है। कार्ड कंपनियां तो वर्षों से दुकानदारों से भुगतान के एवज में कहीं भारी शुल्क वसूलती आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपीआइ सेवा हमेशा से पूरी तरह मुफ्त रही है? कतई नहीं।

प्रत्येक यूपीआइ भुगतान को पूरा करने के लिए करीब दो रुपये की लागत आती है। इस प्रक्रिया में शामिल सर्वर,इंजीनियर,फ्राड चेकिंग से लेकर पलक झपकते ही मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा के लिए किसी और को शुल्क चुकाना पड़ता है। वर्ष 2020 से ही कानून लागू है कि यूपीआइ के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तो इन लागतों का बोझ कौन वहन करता है? इसकी अदायगी पेमेंट कंपनियां और बैंक अपनी जेब से करते हैं और कुछ हद तक करदाता भी। यूपीआइ के लिए सरकार पहले ही करीब 11,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। स्पष्ट है कि कुछ भी पूरी तरह मुफ्त नहीं। फर्क इतना है कि बिल किसी दूसरे पते पर भेजा जाता है।

इस मुद्दे पर इतनी चर्चा क्यों आवश्यक है? ऐसा इसलिए,क्योंकि ऐसे ही कुछ मामलों में भारत के अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। कई राज्यों द्वारा किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ही उदाहरण लीजिए। इससे न तो किसान बहुत फायदे में रहे और न ही बिजली कंपनियां। इसका नतीजा बिजली आपूर्ति में गतिरोध से लेकर ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों में व्यापक खामियों के रूप में सामने आया। मुफ्त बिजली से दिन-रात चलने वाले पंपों के कारण भूमिगत जल पर भी संकट गहराता गया। हमने अपने शहरों में पानी लगभग मुफ्त उपलब्ध कराया हुआ है। इसका नतीजा दिखता है कि नल अमूमन दो घंटे ही चलते हैं। असल में जब किसी सेवा पर राजस्व अर्जित करने के दृष्टिकोण से सीमा तय कर दी जाए तो वह धीरे-धीरे अपनी उपयोगिता गंवा देती है। फिर उसमें न तो कोई निवेश करने के लिए आगे आता है और न ही कोई उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ऐसी सेवा केवल सरकारी अनुकंपा पर चल रही होती है। देखा जाए तो मुफ्तखोरी का चलन ही तमाम अच्छी चीजों के पतन का कारण बनता है। यूपीआइ इससे बेहतर की हकदार है। उसे निरंतर निवेश का सहारा चाहिए। भुगतान का दायरा बढ़ने से सर्वर भी अधिक चाहिए होंगे। धोखाधड़ी बढ़ने से दमदार सुरक्षा आवरण भी आवश्यक है।

पुलिस पर क्यों जनता को विश्वास नहीं?

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पुलिस हमारी रक्षक है ओर पुलिस के कारण ही सभी ओर अमन-चैन ओर शांति बनी रहती है। हरेक नागरिक देश के संविधान का पालन करते हुये आजादी से जिये इसके लिए सरकार ने सभी ओर पुलिस थाने खोल रखे है ओर पुलिस कानून ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी का पालन करती ओर करवाती है लेकिन फिर भी जाने क्यों लोगों का पुलिस से विश्वास उठ गया है। लोग पुलिस को अच्छी नजर से नहीं देखते है ओर भद्दे शब्दों में निंदा करते है। आखिर क्यों काव्यमंचों के संचालक हो या काव्य पाठ करने आए कवि वे खुलेआम पुलिस को चोर, उचक्का,डाकू लुटेरा सहित न जाने क्या क्या उदाहरणों से शर्मनाक तरीके से निंदा कर जनता से वाहवाही लूटकर खुश होते है ओर पुलिस का सार्वजनिक मजाक तालियों की गड़गड़ाहट मे सिवाय पुलिसवाले के किसी ओर को नहीं चुभता है,क्यों? जबकि देखा जाये तो पुलिस दिन रात चौबीस घंटे,सातों दिन,पूरे महीने तीज त्योहारों,पर्वो-उत्सवों,मेलों,रैलियों-जुलूसों ओर सामाजिक व राजनैतिक आयोजनों मे ड्यूटी देकर आपकी सेवा में,भीड़ में सभा में शांति कायम रखने के लिए सतर्क रहती है ओर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाती है,फिर क्या कारण है कि जनता पुलिस से सुविधा-संरक्षण तो चाहती ही पर व्यवहार-आचरण में वह वर्दी के अपमान में जाने अनजाने शामिल रहती है।

साधारण लोग पुलिस के डर से जब तक बहुत ही कष्ट न सह लें तब तक वे छोटी मोटी शिकायतें मुंह पर नहीं लाते । मन की मन ही में रहने देते हैं। किंतु रात में गश्त देने वाले पुलिस कर्मियों की शिकायत जब देखो तभी जिसके देखो उसी के मुंह पर रखी रहती है। इसका क्या कारण है? पुलिस इनमें भेद क्यों करती है तथा पुलिस की नजर में क्या यह आम व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है?क्या पुलिसवाले इतना नहीं जानते कि हम सर्वसाधारण में शांति रखने के लिए रखे गए हैं न कि सताने कुढ़ाने वा चिढ़ाने के लिए ? यदि यह है तो फिर यह पुलिस वाले क्यों ऐसा बर्ताव करने से नहीं बचे रहते जिसमे खुद की निंदा या अपमान हो?

इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग सभी समुदायों में हुआ करते हैं तथा बहुत ही अच्छे बुरे लोग बहुत थोड़े होते हैं। इस नियम से पुलिस वालों में से भी जो कोई दुष्ट प्रकृति का होकर खुद को बेरहम-मक्कार,हरामी भ्रष्ट ओर अब्बल दर्जे का बेईमान बना ले ये ही वर्ग कानून को अपनी पॉकेट में रखकर निंदा का पात्र हो जाता है। इनकी ही निंदा इनके ही कर्म विभाग के अन्य ईमानदार-कर्तव्यनिष्ठ पुलिसवालों के मार्ग में बाधक होने के साथ साथ जगहंसाई का कारण बनते है। जब बिना कारण किसी गरीब-आम नागरिक के लिए पुलिसवाले के कानूनी अधिकार जबरिया प्रताड्ना का कारण बने तो इसकी निंदा होनी चाहिए ओर इस प्रकार के आचरण का बहिष्कार किया जाना चाहिए पर यह नही होता है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों में से प्रशंसा तो कदाचित् कभी किसी बिरले ही के मुख से सुनी जाती है जबकि एक दूसरे के प्रति काम को लेकर प्रतिस्पर्धा होने से वे एक दूसरे की बुराई करने ओर सुनने के अतिरिक्त मीडिया से संपर्क का उसे जगजाहिर कर सुनने-सुनाने ओर पढ़ाने का अवसर नही चूकते है ।

सुरक्षा को लेकर आज जिस प्रकार निजी सुरक्षा एजेंसिया धनाढ्य कालोनियों सहित बड़े व्यवसायिक संस्थानों,बैंकों,निजी भवनों में सुरक्षा गार्ड लगाकर उनसे सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पूरी कराती वे एजेंसी संचालक युवा बेरोजगारों को रोजगार देकर उनकी आधी से ज्यादा तनख़्वाह हजम कर जाते है। कलेक्टर-पुलिस अधीक्षको सहित सभी जिम्मेदारों को पता होता है कि ये सुरक्षाकर्मी पढ़ाई कि डिग्रियों कि मूल प्रति इन्हे देकर नौकरी तो पा जाते है पर आखिर तक वे सुरक्षागार्ड के चक्रव्यूह से मुक्त नही हो पाते ओर डिग्रियों को इनसे प्राप्त करना इनका सपना भर रह जाता है तब आधी

अधूरी तनख्वाह वाले ये युवा तंगी-लाचारी का जीवन जीते हुये हर तीज त्योहारों पर धनिक लोगों से फटा पुराना कपड़ा जूता,अन्य इनके लिए अनुपयोगी हो चुकी सामग्री मांगते है ताकि वे गरीबी में भी अपना ओर परिवार का निर्वाह कर सके। आईएनएस सुरक्षा कर्मी चौकीदार की तनकाह से उनकी बर्दी-जूते के दाम भी कटते है। इस रीति से पूरा वेतन भी नहीं हाथ आता और समय इनकी किस्मत पर थप्पड़ जड़ते रहता है जिससे ये अपनी माता,बहन,भाई सहित बुजुर्ग बीमार पिता आदि का भरण पोषण केवल अपनी कमाई से करना पड़ता है।

पुलिस अधीक्षक,कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर,आबकारी अधिकारी, आरटीओ,सांसद-विध्यक जैसे न जाने कितने अधिकारी व राजनैतिक ओर विभाग प्रमुख होते है जिनके बंगलों सहित निजी घरों में इनके ऑफिसों का 30 प्रतिशत कर्मचारी जो पुलिस-होमगार्ड या विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते है जो इनके बंगलों पर बच्चों को खिलाने,स्कूल लाने ले जाने,खाना बनाने से लेकर सभी तरह की सेवाए देने को विवश होते है जिससे सरकार के एक बड़ा कर्मचारियों का भाग साहब की जी हजूरी में निकाल जाता है, इनमें स्वाभिमानी कर्मचारी तो बच निकलते है किन्तु कुछ तरक्की पाने,अफसरों को प्रसन्न रख अपना उल्लू सीधा करने तो कुछ लाचारी-बेवशी में खामोशी से यह सब सहते है । इन सभी को काम कम से कम दश घंटे करना चाहिए । ऊपर से अबसर पड़ने पर न दिन छुट्टी न रात छुट्टी ।

अपने उच्चाधिकारियों को खुश न रक्खें तो तरक्की कैसी? ठीक नौकरी हो जाए यह भी भय बना रहता है इसलिए सारे कर्मचारी अपने अधिकारी को खुश करने में लगे रहते है, जिनके लिए यह सेवा करना मुश्किल होती है उन्हे दिक्कत झेलना पड़ता है ? इस दशा में सर्वसाधारण को प्रसन्न करें कि अपनी उम्मीद की जड़ सीचे ? हाकिम और रईयत दोनों का खुश रखना बड़े भारी नीतिज्ञ का काम है न कि तीसरे-चौथे वर्ग के पियादे का यह काम है । और गृहस्थों के भ्रमजाल वह हैं जो बड़े-बड़े सेठ रईसों विद्वानों और बुद्धिमानों का मन डावां-डोल कर देते हैं यह बिचारनीय हैं तथा दुनिया का कायदा यह है कि सीधी तरह मुनासिव राशि (रिश्वत)की मांग करे पर वह नही मिलती है तब अगर कोई डर वा लालच दिखा के आडम्बर करके घुस देने आता हो तो मुनासिव की बात छोड़िए मनमाफिक रुपए मिला जाते है। निश्चित ही जब मन की कल्पना से बढ़कर ऊपरी आय हो जाये तो न्याय का विचार छुट जाएगा केवल काम निकालने के अलावा अन्य कोई बात फिर सूझती ही नहीं है।

विचार कीजिये आज कौन पुलिस वाला है जो जो वर्तमान की व्यवस्था से खुश है वह जिस स्थान पर जिस पुलिस थाने के मोहल्ले या वीट में उसकी सेवाए लगाई गई है वहाँ आम लोगों की सेवाए करेगा? कदापि नहीं उसे तो वहाँ से सारे गलत काम करने वाले सटोरिये,जुएवाज,कच्ची पक्की अवैध रूप से बेचने,जैसे कामों के अलावा कानून तोड़ने,क्षेत्र के लोगों को आतंकित करने वालों की सेवाए मिलने लगेगी तो किस बात का संकोच करेगा। पुलिस के आला अफसर को थोड़ी पता है की वह अपने क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है,वह उस क्षेत्र के ऐसे लोगो को सलाम ठोकने जाएगा जो राजनीति में पावर रखते है जो शासन प्रशासन में दखल रकते है उनकी सिफ़ारिश या उनके दो बोल अधिकारियों तक इनके माध्यम से पहुच जाते है,अधिकारी संतुष्ट..कानून व्यवस्था की रोज मईयते निकलती है तो निकलती रहे किसे परवाह है।

महंगाई का जमाना है ओर अब सभी लोगों के महंगे शौक हो गए है। पुलिस आरक्षक से लेकर कोतवाल तक ही नही इसके आगे सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे अधिकारी भी यह मानते है की उन्हे मिलने वाली तनखा से उनका पूरा नही होता है। अब इस नौकरी से जितनी सेवाए जनता की कर सकते है कर रहे है, पर सारी चीजें महंगी हैं और धन कम पड़ने लगा है। नौकरी के अलावा कोई व्यापार तो है नही जो रुपयों की बरसात हो,नौकरी के दौरान अगर कुछ बिना किए सार्थक हो रहा है और कही ना जाये,कुछ किए बिना,न करने के लिए कोई सेवा मिलने से महंगाई डायन से मुक्ति मिले तो इस न करने का लाभ लेने में किस ससुरे को तकलीफ है। जब अफसर न करने का लाभ ले रहे है, जिन्हे जनता की सेवा के लिए ऑफिस में काम करना चाहिए वे सभी कर्मचारी सेवा करने के कारण रिटायर होने तक मर खप के रह जाता है। जनता के रक्षक पुलिस इस तरह उनकी भक्षक बन जाती है तभी तो उन पर से जनता का विश्वास उठ गया है।

यदि सभी विभाग प्रमुख अपने वेतन से नए नौकरों को रखकर अपने बंगले और घरेलू सेवाएं कराने में सक्षम होते हुए भी यह न करे तो यह शोषण का प्रतीक नहीं माना जाएगा। ये अफसर बंगलों से हटाकर अपने ही विभागीय कर्मचारियों की कुंडली पर नाग की तरह बैठे ये उन्हे मिलने वाली तरक्की से वंचित रखते है वहीं फील्ड में उत्कृष्ट काम कर तरक्की पा सकने से उन्हें वंचित रखते है यह भी विचारणीय है। क्या अधिकारी गणों का मानवीय चेहरा सामने आ सकेगा जो छोटे दर्जे के पुलिस या अन्य कर्मचारियों द्वारा विभागों को दी जाने वाली सेवाओं को अपने बंगले- घर पर लेने के कलंक को धो सके,यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह विभाग के लिए ही नही अपितु जनता के लिए भी हर्ष का विषय होगा और बंगलों की सेवाओं से मुक्त हुए कर्मचारी सच्चे मायने में आजाद हो सकेंगे?

नौकरी के साथ जीवन की तैयारी भी जरूरी

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार, हरियाणा

सरकारी नौकरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,लेकिन यह जीवन का सब कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि वेतन,पद,पदोन्नति और सरकारी लाभ अच्छे हैं,लेकिन अच्छा परिवार, स्वास्थ्य,आर्थिक सुरक्षा,व्यक्तिगत विकास और सेवानिवृत्ति के बाद के भविष्य की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सबसे पहले,अपने घर की योजना बनाएं। चाहे गांव हो या शहर,अपना घर होने से स्थिरता और आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। सरकार द्वारा आवास मिलना अच्छी बात है,लेकिन यह आपके जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। अपना घर होने से नौकरी छूटने की स्थिति में आपको और आपके परिवार को काफी आसानी होगी।

काम के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें,लेकिन अपना पूरा जीवन कार्यस्थल को न समर्पित करें। यह न सोचें कि आपके बिना कंपनी नहीं चल सकती। इनमें से प्रत्येक भूमिका कोई और निभा सकता है,लेकिन अपनों के साथ बिताए उन पलों को आप कभी वापस नहीं पा सकते। अपनी छुट्टियों और अवकाश का आनंद लें,आराम करें या परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं,अपना ख्याल रखें,यात्रा करें,सीखें और जीवन का आनंद लें। पदोन्नति को ही सफलता का एकमात्र मापदंड न बनाएं। अभ्यास करें और अपनी क्षमताओं को विकसित करें,ज्ञान बढ़ाएं और अपने हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें। पदोन्नति मिलने पर उसका लाभ उठाएं। अगर पदोन्नति नहीं मिलती है,तो निराश होकर अपने आत्मसम्मान को कम न होने दें। व्यक्तिगत विकास किसी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑफिस की गपशप,राजनीति और नकारात्मक बातों से दूर रहें। बड़ों का आदर करें,लेकिन चापलूसी को अपना पेशा न बनाएं। शक्तिशाली लोगों को खुश करने से क्षणिक सम्मान मिल सकता है;लेकिन ये चीजें स्थायी सम्मान नहीं दिलातीं। अपने आत्मसम्मान,आत्म-सम्मान और आत्मनिर्णय को बनाए रखें।

हमेशा दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक स्तर सुधार के लिए अच्छा होता है,लेकिन अगर यह किसी को हराने की भावना से प्रेरित हो,तो कुछ लोग बेवजह तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपको कल खुद से मुकाबला करना चाहिए, किसी और से नहीं।

अपने वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी तनख्वाह पर निर्भर न रहें और उससे ही सब कुछ पाने की उम्मीद न रखें। अपनी आय, दायित्वों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर बचत और निवेश योजनाएँ बनाएँ। जब आप दूसरी आय या व्यवसाय के बारे में सोचें, तो सुनिश्चित करें कि यह सेवा नियमों और आपके पेशेवर कर्तव्यों के अनुरूप हो।

नियमित रूप से बचत करने की आदत

डालें।अनावश्यक कर्ज और जीवनशैली में बेवजह की बढ़ोतरी से बचें। शिक्षा प्राप्त करने, किसी लाभकारी संपत्ति खरीदने या किसी सुनियोजित उद्यम के लिए उधार लेना भले ही स्वीकार्य हो,लेकिन अपनी मनचाही जीवनशैली बनाए रखने के लिए कर्ज लेना उचित नहीं है।

निजी जीवन की बातें साझा न करें। कार्यालय में निजी संबंधों, आर्थिक मामलों,पारिवारिक मुद्दों और विवाह पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने निजी जीवन के बारे में जो बातें आप साझा करते हैं,उनसे नहीं,बल्किअपने आचरण,पेशेवर रवैये और ईमानदारी से अपने सहकर्मियों,सहयोगियों और नियोक्ताओं का सम्मान करें।

अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि सेवानिवृत्ति 40 या 50 वर्ष की आयु में ही हो। वास्तव में,सेवानिवृत्ति का अर्थ है उन दिनों के लिए वित्तीय,मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना जब काम,चाहे अच्छा हो या बुरा, समाप्त हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रुचियों और गतिविधियों की योजना बनाएं। यह लेखन,अध्यापन,खेती,छोटा व्यवसाय चलाना,सामाजिक कार्य,यात्रा,पढ़ना या कोई अन्य अच्छी गतिविधि हो सकती है। काम करते समय धीरे-धीरे कुछ करने से आपको उसका अनुभव मिलेगा और आप देख पाएंगे कि यह संभव और व्यवहार्य है या नहीं।

अपनी दिनचर्या तय करने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतज़ार न करें। दशकों तक काम करने के बाद,सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में ढलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई और नियमित दिनचर्या या उद्देश्य नहीं होता। सेवानिवृत्ति जीवन का एक नया पड़ाव होना चाहिए, न कि अचानक आने वाला खालीपन।

अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाएं। कोई किताब पढ़ें, कोई नया कौशल सीखें, कोई व्यक्तिगत परियोजना शुरू करें, परिवार के साथ यात्रा करें,स्वस्थ रहें या कोई शौक अपनाएं। आप अपना समय कैसे बिताते हैं,यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपना जीवन कैसे जिएंगे।

सेवानिवृत्ति और पेंशन के लिए बचत करना न भूलें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बचत आपके स्वास्थ्य,सम्मान,स्वतंत्रता और वृद्धावस्था में आपकी ज़रूरतों की रक्षा करें। सेवानिवृत्ति के बाद अच्छे वित्तीय निर्णय लेना महत्वपूर्ण है,जिसमें स्वास्थ्य देखभाल,घर और व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरतों और आपातकालीन खर्चों के भविष्य के खर्चों को ध्यान में रखा जाए।

जब आप सेवानिवृत्त हों,तो जीवन से सेवानिवृत्त न हों। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब आप उन सभी चीजों पर ध्यान दे सकें जो आप नौकरी के दौरान नहीं कर पाए थे। एक सुबह चाय पीते हुए,धूप में किताब पढ़ते हुए,यात्रा करते हुए,परिवार के साथ समय बिताते हुए,अपनी पसंद की चीजें करते हुए,समाज की सेवा करते हुए या चाहें तो छोटा व्यवसाय चलाते हुए बिताएं।

याद रखें कि कार्यस्थल सुरक्षित नहीं है। नौकरी बदल सकती है,कार्यालय बदल सकता है,और कभी-कभी कार्यालयों को स्थानांतरित भी करना पड़ सकता है। आपके पास केवल आपकी क्षमता,आपकी बचत,आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य,आपकी प्रतिष्ठा और आपका जीवन ही शेष रह जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम का आनंद लें,लेकिन काम को अपने जीवन पर हावी न होने दें। ईमानदारी से काम करें और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानें,अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, आर्थिक सुरक्षा बनाएं और समय रहते भविष्य के लिए योजना बनाएं।

काम में सफल होना केवल एक अच्छा कामकाजी जीवन प्रदान करने वाला करियर नहीं है। एक सफल करियर वह है जो आपको एक अच्छा जीवन बनाने में मदद करता है-काम के दौरान भी और काम छोड़ने के बाद भी।

प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर क्यों भड़का विपक्ष

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया भाषण देश की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा...कि सरकार ने हथियार उठाने वाले नक्सलियों को लगभग समाप्त कर दिया है,लेकिन देश के भीतर अब एक नया खतरा पैदा हो गया है,जिसे उन्होंने दिमागी नक्सली कहा। उनके अनुसार,ये लोग बंदूकों से नहीं,बल्कि अपनी विचारधारा और विमर्श से देश को नुकसान पहुंचाने और युवाओं को गुमराह करने की ताक में रहते हैं। इस बयान के आते ही भारतीय राजनीति में एक भूचाल-सा आ गया। विपक्षी दलों ने इस शब्दावली को एक बड़े हथियार के रूप में लपक लिया और सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के एक बड़े बयान से हुई, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते आम आदमी पार्टी और कई अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी खुद को इस श्रेणी में खड़ा करना शुरू कर दिया। नेताओं द्वारा खुद को दिमागी नक्सली बताने की यह होड़ सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है,बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक बिसात और रणनीतियां छिपी हुई हैं, जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पहला और गहरा असर राजनीतिक विमर्श के स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल उन लोगों को घेरने के लिए किया था,जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और जिनके बारे में सत्ता पक्ष का मानना है कि वे देश के विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस आक्रामक हमले को एक रक्षात्मक कवच में बदल दिया। पी. चिदंबरम और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा खुद को दिमागी नक्सली कहना वास्तव में सरकार की परिभाषा का मज़ाक उड़ाना और उसकी धार को कुंद करना है। विपक्ष का यह कदम यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर सरकार पर सवाल उठाना,नीतियों की आलोचना करना और युवाओं को जागरूक करना नक्सलवाद है,तो वे गर्व से इस ठप्पे को स्वीकार करते हैं। इससे देश की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा हो गया है,जहां एक तरफ सरकार देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर असहमति को दबाने का प्रयास करती दिख रही है,वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस असहमति को लोकतंत्र की आत्मा बताकर खुद को पीड़ित और क्रांतिकारी के रूप में पेश कर रहा है।

इस राजनीतिक उठापटक का दूसरा बड़ा पहलू युवाओं और देश के बौद्धिक वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विशेष रूप से युवाओं का जिक्र किया था कि उन्हें ये दिमागी नक्सली भटका रहे हैं। भारत एक युवा-प्रधान देश है और युवाओं की राय चुनाव के नतीजों को पलटने की ताकत रखती है। विपक्ष द्वारा खुद को दिमागी नक्सली बताना युवाओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर सकता है,खासकर उन छात्रों और बुद्धिजीवियों को,जो विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा नीतियों,बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस करते हैं। जब बड़े नेता खुद पर यह ठप्पा लगाते हैं,तो वे युवाओं को यह अहसास कराते हैं कि स्थापित व्यवस्था के खिलाफ सोचना या सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। इसके विपरीत, सत्ता पक्ष इस विमर्श को स्थापित करने में जुटेगा कि विपक्ष देश के विकास को पटरी से उतारने वाली ताकतों के साथ खड़ा है। यह खींचतान देश के युवाओं के बीच वैचारिक विभाजन को और गहरा करेगी,जिससे वे रचनात्मक विमर्श के बजाय राजनीतिक खेमेबाजी का हिस्सा बनने लगेंगे। तीसरा बड़ा असर देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की राजनीति पर पड़ेगा। अब तक नक्सलवाद को एक भौगोलिक और हथियारबंद समस्या के रूप में देखा जाता था, जिसे पुलिस और सेना के जरिए हल किया जा रहा था। लेकिन अब जब यह लड़ाई दिमाग और विचारधारा के स्तर पर आ गई है,तो सरकार की जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। विपक्ष का डर यह है कि दिमागी नक्सली की आड़ में सरकार अपने आलोचकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को निशाना बना सकती है।

शीशे का चश्मा

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

सदर तहसील कार्यालय के मुख्य प्रांगण में पचहत्तर साल के जगन्नाथ जी हर दिन सुबह ठीक दस बजे आकर खड़े हो जाते थे। वह कार्यालय जहाँ ईमानदारी केवल नोटिस बोर्ड पर चिपकी रहती है और भ्रष्टाचार फाइलों के भीतर एयरकंडीशंड हवा खाता है वहां उनका आगमन किसी पुराने पाप की तरह लगता था। उनके हाथ में प्लास्टिक का एक पुराना ऐनक का ढांचा होता था जिसका बायां शीशा गायब था और दाहिनी तरफ केवल एक धुंधला कांच बचा हुआ था जिसे देखकर लगता था कि व्यवस्था ने उनकी एक आंख का मोतियाबिंद तो ठीक किया पर दूसरी आंख का वजूद ही डकार लिया। तहसील का नया चपरासी जो साहबों की जूठन और अहंकार चाटकर खुद को आधा तहसीलदार समझने लगा था उन्हें धूप में खड़ा देखता तो चुटकी लेते हुए कहता कि बाबा जब चश्मे का एक शीशा फूट ही गया है तो इसे रोज़ अपनी हथेली पर सजाकर यहाँ अफ़सरों का रास्ता क्यों रोकते हो क्या अपनी दरिद्रता का विज्ञापन कर रहे हो। जगन्नाथ जी अपनी झुर्रियों से ढकी धुंधली आँख से उस एक शीशे के पार देखने की कोशिश करते और बहुत शांत स्वर में उत्तर देते कि बेटा यह टूटा हुआ चश्मा केवल कांच का टुकड़ा नहीं है बल्कि इस पूरे महकमे की वो एकतरफा दृष्टि है जिसे दुनिया का सच कभी पूरा दिखाई ही नहीं देता क्योंकि सच देखने के लिए ज़मीर की ज़रूरत होती है और यहाँ ज़मीर कब्ज़ का शिकार होकर फाइलों में दफन है। दफ़्तर में आने वाले तमाम मुंशी जो मुवक्किलों का खून चूसकर लाल हो रहे थे और फरियादी जिनका खून सूख चुका था उनका उपहास उड़ाते हुए कहते कि लगता है बूढ़े का दिमाग पूरी तरह सठिया चुका है जो एक आंख से सरकारी इमारत को घूरकर अपना काम कराना चाहता है जबकि यहाँ तो चार आंखों वाले भी अंधे होकर मेज़ के नीचे हाथ फैलाते हैं। जगन्नाथ जी किसी की कड़वी बात का बुरा माने बिना उस एक शीशे वाले चश्मे को अपनी फटी हुई धोती के कोने से पोंछते जो खुद व्यवस्था की तरह तार तार हो चुकी थी और चुपचाप पीपल के पेड़ की छांव में खड़े रहकर फ़ाइलों का इंतज़ार करते रहते थे मानों वह फाइलें न होकर मोक्ष का मार्ग हों।

जगन्नाथ जी की यह अनूठी दिनचर्या पिछले दो सालों से बिना किसी नागा के जारी थी क्योंकि सरकारी तंत्र में काम रुकने की गारंटी होती है पर चलने की कोई उम्मीद नहीं होती। दफ़्तर का बड़ा बाबू जब भी अपनी चमकती कार से उतरता जो दरअसल आम जनता की हड्डियों के चूरे से बनी सड़क पर दौड़ती थी तो जगन्नाथ जी उसके सामने वही टूटा हुआ चश्मा आगे बढ़ा देते और कहते कि बाबू जी क्या आज मेरी ज़मीन के उस टुकड़े का सही नक्शा बन गया। बाबू चिढ़कर चश्मा ठीक करता और गुस्से में चिल्लाकर कहता कि अरे बूढ़े जब तक सर्वेक्षण की टीम दोबारा गाँव नहीं जाएगी और पटवारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी जिसे दर्ज करने के लिए पटवारी को दक्षिणा की ज़रूरत है तब तक कागज़ में एक इंच भी बदलाव नहीं होगा और तुम इस टूटे ऐनक को लेकर ताउम्र यहाँ चक्कर काटते रहोगे क्योंकि यहाँ कागज़ नहीं बल्कि नोट बोलते हैं। जगन्नाथ जी बिना कोई विरोध दर्ज कराए उस ऐनक को अपने पुराने सूती झोले में सहेजते और गाँव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर चुपचाप पैदल ही निकल पड़ते थे जो सड़क शायद कागज़ों पर तीन बार पक्की बनकर अफ़सरों के पेट में पच चुकी थी। गाँव के लोग आपस में तरह तरह की चर्चाएँ करते थे कि आखिर एक मामूली टूटे हुए ऐनक और तहसील के उस नक़्शे के बीच ऐसा कौन सा अटूट रिश्ता है जिसकी खातिर एक वयोवृद्ध इंसान रोज़ अपनी कांपती टांगों के सहारे पाँच किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके उस सरकारी चौखट पर हाजिरी लगाता था जहाँ देवता नहीं बल्कि राक्षसों के आधुनिक अवतार कुर्सी तोड़ते थे।

एक दिन अचानक ज़िले के नए जिलाधिकारी महोदय तहसील के वार्षिक कामकाज का जायज़ा लेने के लिए औचक निरीक्षण करने पहुँच गए जैसे किसी मरे हुए चूहे की गंध सूंघने कोई शिकारी कुत्ता आता है। दफ़्तर में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए फ़ाइलों को अलमारियों में ऐसे दबाने लगे जैसे मुजरिम लाश को ज़मीन में गाड़ता है ताकि गवाह न बचे। निरीक्षण के बाद जब जिलाधिकारी महोदय पत्रकारों की भीड़ के साथ बाहर निकले जो उनकी आरती उतारने को उतावले थे तो उनकी नज़र पीपल के पेड़ के नीचे खड़े जगन्नाथ जी पर पड़ी जिनके हाथों में वही टूटा हुआ ऐनक चमक रहा था। जिलाधिकारी महोदय ने अपनी जनप्रिय छवि को चमकाने के लिए मीडिया कर्मियों को आगे किया ताकि उनकी दयालुता का लाइव टेलीकास्ट हो सके और बाबा के करीब जाकर बड़े आदर से पूछा कि बाबा आप इस तेज़ धूप में यह एक शीशे वाला चश्मा लेकर क्यों खड़े हैं क्या दफ़्तर के लोग आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं बताइए मैं अभी आपकी समस्या का समाधान करवाता हूँ क्योंकि समाधान का आश्वासन देना ही प्रशासन की पहली और आखिरी कला है। जगन्नाथ जी ने अपनी सूजी हुई आँखों से साहब की तरफ देखा और अपने थरथराते हाथों से वह टूटा चश्मा जिलाधिकारी महोदय की हथेली पर रखते हुए बोले कि साहब जी ज़रा इस चश्मे को अपनी आँखों पर लगाकर उस सामने टंगे हुए नए हाईवे के नक़्शे को देखिए जिसे देखकर विकास की गंगा बह रही है। जिलाधिकारी महोदय ने अचंभित होकर उस एक शीशे वाले ऐनक को अपनी आँखों पर लगाया तो उन्हें नक़्शे का केवल एक ही हिस्सा साफ़ दिखाई दिया और बाकी आधा हिस्सा पूरी तरह ओझल हो गया जैसे जनता के अधिकारों पर सरकारी गोपनीयता का परदा पड़ा हो। जगन्नाथ जी की आँखों से आंसुओं के मोटे कतरे ढलककर उस ऐनक के ढांचे पर गिर पड़े और वे रुंधे गले से बोले कि साहब दो साल पहले जब आपकी सड़क योजना का नक़्शा बना तो अफ़सरों ने एक शीशे वाले चश्मे से देखकर मेरे छोटे से मकान को सरकारी ज़मीन बता दिया क्योंकि गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा करना पुण्य का काम माना जाता है और दबंगों के बड़े फार्महाउस को बख्श दिया क्योंकि उनकी तिजोरियों की चमक अफ़सरों की दूसरी आँख फोड़ देती है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

कुम्हरता दोहरे हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

16 गवाह और 46 आर्टिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला,वैज्ञानिक साक्ष्यों से मजबूत हुई अभियोजन की कहानी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में अक्टूबर 2025 में हुए बहुचर्चित पति-पत्नी हत्याकांड में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,अंबिकापुर की अदालत ने 14 अगस्त 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले के दोनों आरोपियों करीमन मझवार (42),निवासी पम्पापुर और जय श्याम (28),निवासी पम्पापुर को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

घर की परछी में मिले थे पति-पत्नी के शव : मामला दरिमा थाना के अपराध क्रमांक 159/2025 से संबंधित है। 22-23 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात ग्राम कुम्हरता घाधी में पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। 23 अक्टूबर की सुबह सूचना मिलने पर दरिमा पुलिस मौके पर पहुंची,जहां रीमा लकड़ा एवं जुली लकड़ा उर्फ उर्मिला के शव घर की परछी में मिले। जांच में हत्या के साथ घर से बकरियां गायब होने की बात भी सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल घटनास्थल पहुंचे और पुलिस टीम को बारीकी से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की पतासाजी के निर्देश दिए।

16 गवाह और 46 आर्टिकल साक्ष्य बने आधार : विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर 2025 को अभियोग पत्र क्रमांक 164/2025 न्यायालय में पेश किया। आरोपियोंके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) दो बार, धारा 3(5) तथा धारा 332(क) के तहत आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 16 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और 46 आर्टिकल साक्ष्य प्रस्तुत किए। परिस्थितिजन्य एवं भौतिक साक्ष्यों के साथ अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

टांगी और खून लगे कपड़े मिले अहम साक्ष्य

विवेचना के दौरान पुलिस ने करीमन मझवार और जय श्याम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर घटना में प्रयुक्त टांगी (कुल्हाड़ी) बरामद की गई। घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए शर्ट भी जब्त किए गए,जिन पर खून जैसे धब्बे पाए गए थे। इसके अलावा घटनास्थल से शवों के पास मिली खून आलूदा मिट्टी,साधारण मिट्टी,मृतकों के कपड़े और पोस्टमार्टम के दौरान संरक्षित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए गए। सभी साक्ष्यों को परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया तथा हथियार और कपड़ों का क्यूरी परीक्षण भी कराया गया।

उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की अनुशंसा

न्यायालय ने मृतकों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में भी विचार किया। निर्णय में मृतकों की क्षति को अपूरणीय बताते हुए उनके उत्तराधिकारियों को समुचित प्रतिकार प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है।

विवेचक और पुलिस टीम को मिलेगा पारितोषिक

दोहरे हत्याकांड की विवेचना में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा से विवेचक एवं सहायक स्टाफ को उचित पारितोषिक देने की अनुशंसा की थी। इसके बाद आईजी दीपक झा ने प्रकरण के विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजेश खलखो सहित विवेचना में सहयोग करने वाले दरिमा थाना स्टाफ के उत्साहवर्धन के लिए उचित पारितोषिक देने की घोषणा की है। एसएसपी राजेश अग्रवाल ने न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए विवेचक थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक राजेश खलखो की उच्च व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट विवेचना की सराहना की।

साइबर जागृति अभियान में 700 छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

OTP,UPI,फर्जी लिंक,APK,सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट से बचाव की दी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

साइबर अपराधों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत मंगलवार को जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डीआईजी/एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व साइबर सेल के नोडल अधिकारी रितेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में करीब 700 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरबार,शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, आईटीआई लखनपुर,राजकुमार कॉलेज उदयपुर, पुलिस लाइन हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, कंप्यूटर सेंटर मणीपुर एवं कन्या छात्रावास स्कूल रोड में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को OTP,UPI एवं QR Code फ्रॉड,फर्जी लिंक, APK फाइल,फर्जी कस्टमर केयर नंबर,सोशल मीडिया फ्रॉड,फर्जी प्रोफाइल,अनजान वीडियो कॉल, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों को समझाया गया कि OTP,PIN,CVV,पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें तथा अनजान लिंक पर क्लिक या किसी के कहने पर QR Code स्कैन न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करने तथा cybercrime.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई। पुलिस ने बताया कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान 'जागरूकता की एक Selfie' अभियान के तहत विद्यार्थियों को QR Code के माध्यम से साइबर जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

छात्र-छात्राओं ने QR Code के साथ Selfie लेकर अभियान में सहभागिता की। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ पुलिस मितान एवं साइबर वॉलंटियर टीम के अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता, आस्था गुप्ता, विभाश्री सिंह एवं राजकुमार ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। विद्यार्थियों ने साइबर अपराधों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका पुलिस टीम ने समाधान किया। अंत में विद्यार्थियों ने स्वयं जागरूक रहने तथा परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। पुलिस ने संदेश दिया कि सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में संजीव मंडल को उम्रकैद

गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला..33 गवाहों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि,आर्म्स एक्ट में भी 5 साल की सजा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने करीब दो साल से चले मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संजीव मंडल उर्फ भानू बंगाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद तथा आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से 33 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

20 अगस्त 2024 को जंगल में मिली थी लाश

अंबिकापुर के चर्चित स्टील कारोबारी परिवार से जुड़े अक्षत अग्रवाल की 20 अगस्त 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहर से लगे चठिरमा जंगल में उनकी कार के अंदर शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच में अक्षत को गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए संजीव मंडल को हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किए थे। पुराने पुलिस खुलासे के अनुसार आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल तथा कारतूस बरामद हुए थे। मृतक के सोने के आभूषण और नकदी भी आरोपी से बरामद होने की बात सामने आई थी।

आरोपी ने दिया था चौंकाने वाला बयान

पुलिस पूछताछ के दौरान संजीव मंडल ने ऐसा दावा किया था,जिसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया था। आरोपी का कहना था कि अक्षत ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। उसके मुताबिक इसके बदले उसे 50 हजार रुपये और सोने के आभूषण दिए गए थे तथा अक्षत स्वयं उसके साथ सुनसान स्थान पर गया था। पुलिस के सामने आरोपी अपने इस बयान पर लगातार कायम रहा। कई दौर की पूछताछ और रिमांड के बावजूद उसके बयान में बदलाव नहीं आया। इसी कारण जांच एजेंसियों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी ही हत्या की सुपारी क्यों देगा। उस समय मृतक के परिजनों ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की गहराई से जांच की मांग की थी।

नार्को और ब्रेन मैपिंग तक पहुंची जांच

आरोपी के लगातार एक ही बयान पर कायम रहने के बाद पुलिस ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए वैज्ञानिक जांच का सहारा लिया। न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपी के नार्को टेस्ट,ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सितंबर 2024 में पुलिस की ओर से बताया गया था कि नार्को टेस्ट छत्तीसगढ़ में तथा ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर स्थित एफएसएल में कराया जाना था। मामले की जांच में वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। अभियोजन ने अदालत के समक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अंततः अदालत ने अभियोजन के पक्ष में फैसला देते हुए आरोपी को हत्या का दोषी माना।

हथियार और कारतूस बरामदगी भी बनी अहम कड़ी

हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल,कारतूस,नकदी तथा मृतक के आभूषण बरामद किए थे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से ऑटोमैटिक पिस्टल और कारतूस बरामद किए जाने की जानकारी दी थी। बरामद हथियारों को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई गई थी। पुलिस के सामने यह सवाल भी था कि हथियार आरोपी तक कैसे पहुंचे और हत्या के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने उपलब्ध भौतिक, फॉरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

33 गवाहों की गवाही ने मजबूत किया अभियोजन का पक्ष : अदालत में अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अलावा फॉरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष रखा गया। इन सभी साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के बाद न्यायालय ने संजीव मंडल को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को अक्षत अग्रवाल के परिजनों के लिए लंबे समय से चले आ रहे न्यायिक संघर्ष के बाद महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

हाईप्रोफाइल हत्याकांड ने खड़े किए थे कई सवाल : अक्षत हत्याकांड की शुरुआत से ही यह मामला कई सवालों के कारण सुर्खियों में रहा। एक ओर पुलिस के सामने हत्या का रहस्य था, वहीं दूसरी ओर आरोपी का यह दावा कि मृतक ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी, जांच की सबसे बड़ी पहेली बन गया था। घटना के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा हुई थी।

तत्कालीन पुलिस जांच पर सवाल उठाए जाने के बाद वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया। अब अदालत के फैसले के साथ इस चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी को हत्या और हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई गई है। न्यायालय के फैसले ने करीब दो साल पुराने इस मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव तय किया है।

तहसील परिसर में व्यवस्था के नाम पर खाली मैदान,न बाउंड्री न बैठने की जगह

जमीन की रजिस्ट्री कराने आएं तो धूप-बारिश में खड़े रहिए,शौचालय जाना हो तो रास्ता तलाशिए,सुरक्षा भी भगवान भरोसे

सुदामा राजवाड़े

राजपुर (बलरामपुर),18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरकार भले ही आम लोगों को बेहतर प्रशासन और सुविधाएं देने के दावे करती हो, लेकिन राजपुर तहसील कार्यालय परिसर की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आती है। यहां रोजाना दूर-दराज के गांवों से अपनी जमीन,राजस्व और अन्य सरकारी काम लेकर पहुंचने वाले ग्रामीणों के लिए न ढंग की बाउंड्री है,न प्रतीक्षालय और न सुलभ शौचालय। ऊपर से साफ-सफाई की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। विडंबना यह है कि जिस परिसर में लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने पहुंचना होता है, वहीं उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए खुद संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि तहसील कार्यालय जनता की सुविधा के लिए है या जनता की परीक्षा लेने के लिए?

चारदीवारी नहीं,इसलिए परिसर में वाहन ही वाहन

तहसील परिसर की बाउंड्री वॉल नहीं होने से कार्यालय परिसर और सड़क के बीच कोई स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती। दोपहिया और चारपहिया वाहन बेधड़क परिसर में आते-जाते रहते हैं। ऐसे में कार्यालय में मौजूद ग्रामीणों,महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब एक वर्ष पहले राजपुर नगर पंचायत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी तहसील कार्यालय से निकलते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। यानी हादसा हो जाए तो चर्चा, उसके बाद फिर वही पुरानी व्यवस्था–मानो प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार हो।

रजिस्ट्री कराने आएं तो 'वेटिंग रूम' नहीं,पेड़ की छांव सही : तहसील परिसर में उप-पंजीयक कार्यालय भी संचालित होता है। जमीन की रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजी कामों के लिए रोज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन उनके बैठने या प्रतीक्षा करने के लिए कोई समुचित प्रतीक्षालय नहीं है। बारिश हो तो पानी से बचने की जद्दोजहद और धूप हो तो छांव तलाशना–यही यहां आने वाले लोगों की दिनचर्या बन गई है। बुजुर्ग और महिलाएं घंटों खड़े रहने को मजबूर होते हैं। व्यंग्य यही है कि सरकारी दफ्तर में काम कराने आए नागरिकों के लिए 'वेटिंग शेड' की सुविधा नहीं, लेकिन इंतजार जरूर भरपूर है।

महिलाओं और बुजुर्गों की सबसे ज्यादा परेशानी : तहसील परिसर में सुलभ शौचालय नहीं होने से दूर-दराज से आने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक ओर शासन स्वच्छता और महिला सम्मान की बात करता है,वहीं दूसरी ओर तहसील जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय में बुनियादी शौचालय सुविधा का अभाव व्यवस्था की गंभीर कमी को दर्शाता है।

कचरा पेटी की जगह खोद दिया 'कचरा गड्ढा' : साफ-सफाई की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। उप-पंजीयक कार्यालय के दरवाजे के सामने व्यवस्थित डस्टबिन रखने के बजाय गड्ढा खोदकर कचरा डाले जाने की शिकायत है। इससे गंदगी और दुर्गंध के साथ संक्रमण का खतरा भी बना रहता है।

विडंबना देखिए–जिस कार्यालय में लोग जमीन-जायदाद के दस्तावेज सुरक्षित कराने पहुंचते हैं,उसके सामने कचरा खुले गड्ढे में 'स्थायी पता' बना चुका है।

स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखकों का भी दर्द : तहसील परिसर में काम करने वाले स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखकों का कहना है कि तहसील कार्यालय शुरू होने के बाद से ही यहां की बुनियादी व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। रोजाना अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर के सामने अव्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं दिखती।

बड़ा सवाल...हादसे के बाद जागेगा प्रशासन? तहसील कार्यालय कोई सामान्य परिसर नहीं, बल्कि ऐसा सार्वजनिक केंद्र है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और नगरवासी अपने जरूरी सरकारी कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बाउंड्री वॉल, प्रतीक्षालय,शौचालय और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं किसी विलासिता की चीज नहीं,बल्कि न्यूनतम आवश्यकता हैं। अब सवाल स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से है–क्या किसी बड़े हादसे या जनआक्रोश के बाद ही तहसील परिसर की तस्वीर बदलेगी? या उससे पहले ही यहां सुरक्षित, स्वच्छ और सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी?

एसडीएम से संपर्क का प्रयास,नहीं उठा फोन : इस संबंध में राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान से उनके मोबाइल नंबर 62603 60570 पर संपर्क कर तहसील परिसर की अव्यवस्थाओं और आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

फिलहाल राजपुर तहसील परिसर की तस्वीर यही सवाल पूछ रही है... ***जनता सुविधा लेने तहसील पहुंच रही है या सुविधा तलाशने?***

हाथी हमारे दुश्मन नहीं,मित्र हैं : वन विभाग

विश्व हाथी दिवस पर सरहरी स्कूल में जन-जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों व ग्रामीणों को बताए हाथियों से बचाव के उपाय

-संवाददाता-
प्रतापपुर,18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

वन मंडल सूरजपुर के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और ग्रामीणों को मानव-हाथी सह-अस्तित्व के प्रति जागरूक करना और हाथियों से बचाव के सुरक्षित उपायों की जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य दिलीप तिवारी के स्वागत उद्बोधन से हुई। उप वनमंडलाधिकारी संस्कृति बारले ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को हाथियों के व्यवहार की जानकारी देते हुए बताया कि हाथी के नजदीक आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने लोगों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उन्हें किसी भी स्थिति में छेड़ने या उकसाने से बचने की अपील की। वन विभाग के कर्मचारियों ने भी हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने कहा कि हाथी हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि मित्र हैं। जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए इनके साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जरूरी है। शिक्षक अविनाश तिवारी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में व्याख्याता विजय भारती ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

वन्यजीव संरक्षण की ली शपथ : अजय चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को वन्यजीव संरक्षण की शपथ दिलाई। सभी ने हाथियों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा हाथी दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने का संकल्प लिया। इस दौरान 'हाथी बचाएं- जंगल बचाएं, जंगल बचाएं- जीवन बचाएं' का संदेश दिया गया।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत : कार्यक्रम के दौरान पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर आयोजित चित्रकला, निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। चित्रकला में कक्षा आठवीं की वंदना सिंह प्रथम, कक्षा सातवीं के मोहन कुशवाहा द्वितीय और कक्षा छठवीं की रागिनी मिश्रा तृतीय रहीं। हाईस्कूल निबंध प्रतियोगिता में कक्षा नौवीं की सृष्टि यादव प्रथम, कक्षा दसवीं की दीपिका यादव द्वितीय और कक्षा नौवीं की पूजा राजवाड़े तृतीय रहीं। हायर सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 11वीं की प्राची यादव प्रथम, रजनी द्वितीय और कक्षा 12वीं की फूलपत्तियां तृतीय रहीं। सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा।

सरगुजा में मूसलाधार बारिश,दो दिन और भारी बारिश के आसार...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा सहित पूरे संभाग में पिछले दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। अंबिकापुर में मंगलवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 46.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मानसून सीजन में अब तक कुल वर्षा का आंकड़ा 900 मिमी के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसके अगले दो दिनों तक सक्रिय रहने की संभावना है। इसके चलते सरगुजा संभाग सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ग्रामीण और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अगस्त को सरगुजा सहित कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार

गांधीनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई,घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय आरोपी महेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अगस्त 2026 को कोटछाल,सीतापुर निवासी एवं वर्तमान में चठिरमा में रहने वाले महेश्वर गुप्ता ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत आशय से छेड़छाड़ की। शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 519/2026 के तहत बीएनएस की धारा 137(2), 74 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों से संबंधित गंभीर अपराधों में त्वरित और सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर उप निरीक्षक दिलीप दुबे,प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय,सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, आरक्षक सुरेश पैकरा एवं मोतीलाल सक्रिय रहे।

बाइक से गिरकर घायल महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मोटरसायकल के चेन में साड़ी फंसने से महिला गिर गई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। निजी अस्पताल से इलाज करने के बाद रिफर करने पर स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे,यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बटवाही की अवध कुमारी यादव पति स्व. राजेन्द्र यादव 41 वर्ष,16 अगस्त को अपने देवर रविन्द्र यादव के साथ गांव में ही धान की फसल देखने के लिए मोटरसायकल से जाने निकली थी। सुबह करीब 9 बजे गांव के बिंझियापारा में बाइक में पीछे बैठी महिला का साड़ी चेन में फंस गया, और वह सडक़ पर गिर गई, जिसमें उसे सिर में चोट आई थी और बेहोश हो गई थी। रविन्द्र इसकी जानकारी भतीजा संजय सहित परिवार के अन्य सदस्यों को दिया। स्वजन उसे निजी वाहन से अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे,यहां से 17 अगस्त को चिकित्सक ने उसे रायपुर ले जाने की सलाह दी थी। स्वजन स्थिति नाजुक देख उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

अपर कलेक्टर पर प्लेसमेंट कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

सुपरवाइजर बोला-गड्ढा खोदकर गाड़ देने की दी धमकी,कर्मचारियों ने थाने पहुंचकर की शिकायत; आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
सूरजपुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर के अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर विश्रामपुर नगर पंचायत के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने मारपीट करने और गड्ढा खोदकर गाड़ देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित दर्जनभर से अधिक कर्मचारी शिकायत करने विश्रामपुर थाने पहुंचे। कर्मचारियों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार विश्रामपुर में 15 अगस्त से लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से मरीजों का पंजीयन और उपचार किया जा रहा है। बारिश के कारण ट्रेन तक पहुंच मार्ग में कीचड़ होने से एंबुलेंस के आवागमन के लिए रास्ता तैयार कराया जा रहा था। तहसीलदार के निर्देश पर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगर पंचायत के प्लेसमेंट कर्मचारी रास्ता बनाने में जुटे थे। इसी दौरान अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे।

प्लेसमेंट कर्मचारी सुपरवाइजर आकाश सिन्हा का आरोप है कि अपर कलेक्टर ने उनसे गोलू के संबंध में पूछताछ की। कर्मचारी ने खुद को केवल मजदूर बताते हुए रास्ता बनाने का काम करने की बात कही। आरोप है कि इस पर अपर कलेक्टर ने गड्ढा खोदकर गाड़ देने और ऊपर से जेसीबी चलवा देने की धमकी दी। इसके बाद गार्ड की मदद से उन्हें गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया और विरोध करने पर थप्पड़ व हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।

फोन तोडऩे का भी आरोप : कर्मचारियों का आरोप है कि घटना की जानकारी कार्यालय में देने के लिए कर्मचारी रितेश ने फोन निकाला तो उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि वे काम करने आए हैं,किसी की मार खाने नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में करीब आधे घंटे तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कर्मचारियों ने कहा कि मामले की शिकायत सूरजपुर कलेक्टर से की जाएगी। वहां भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

अपर कलेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद : अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा ने मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मौके पर सभी कर्मचारियों को अपना काम करने के निर्देश दिए थे। निर्देश थोड़े तल्ख लहजे में दिए गए होंगे,जिसे कुछ लोग अन्यथा ले रहे हैं। मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं।

अंबिकापुर में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का भूमिपूजन

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से किया भूमिपूजन व शिलान्यास

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। अंबिकापुर में प्रस्तावित नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के लिए न्यायालय परिसर में भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से भवन का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। समारोह में हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू तथा सरगुजा जिले के पोर्टफोलियो जज जस्टिस राजेश राय सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने नवीन न्यायालय भवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय भवन को अपने घर की तरह समझें और न्यायिक कार्य को पूरी निष्ठा से करें। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार अंबिकापुर आए थे,तब जिला न्यायालय भवन की स्थिति देखकर ही उन्होंने नए भवन के निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके विशेष प्रयास और रुचि के कारण ही सरगुजा में नवीन जिला न्यायालय भवन के निर्माण का कार्य आगे बढ़ सका। समारोह के दौरान नवीन न्यायालय भवन के शिलालेख का वर्चुअल अनावरण भी किया गया।

इसके बाद विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ। नवीन भवन के निर्माण से न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ अधिवक्ताओं और पक्षकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा,कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल,जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका की अधोसंरचना में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण से सरगुजा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अधोसंरचना की मांग पूरी होने की उम्मीद है।

पानी भरे गड्ढे में गिरने से महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मणिपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर चैक में रहकर कबाड़ बिनने वाली महिला पानी भरे नालीनुमा गड्ढे में गिर गई, अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक,बिलासपुर जिला के लालखदान का गजेन्द्र कुमार साहू वर्तमान में अंबिकापुर के बिलासपुर चैक के पास एक झोपड़ी में अपनी पत्नि नीतू साहू 36 वर्ष व मां के साथ रहकर मजदूरी और कबाड़ बिनने का काम करता था। इनके दो छोटे बच्चे हैं। मृतिका के पति का कहना है कि उसकी पत्नि सिकलिन बीमारी से पीड़ित थी,और शरीर में 4-5 ग्राम खून था। इसे कुछ दिन पहले ही वह खून चढ़वाया था। बीते एक सप्ताह से उसकी पत्नि की तबियत खराब थी। 16 अगस्त को उसकी पत्नि शाम को करीब 4-5 बजे पीने का पानी भरने के लिए घर के पीछे गई थी,इसके बाद नहीं लौटी। पत्नि के खोजबीन में लगा था,इसी बीच उसे पता चला कि उसके ठिकाना के पीछे पानी में कोई गिरा है,जब वह मौके पर गया तो उसकी पत्नि थी। इसे उठाकर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लाया, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

बाइक से गिरकर घायल ग्रामीण की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मोटरसायकल से अनियंत्रित होकर गिरे दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम गोरयापीपर निवासी बुधराम मझवार पिता आनन्द मझवार 52 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बीते 15 अगस्त को बाइक से ग्राम कुसु जा रहा था। रास्ते में बाइक के अनियंत्रित होने से गिरकर वह जख्मी हो गया था। इसकी सूचना स्वजन को मोबाइल फोन पर मिली और वे उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे थे। अस्पताल प्रबंधन से मिली मौत की सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

धौरपुर में डबल मर्डर: बेटे ने कुल्हाड़ी से माता-पिता को मार डाला

शवों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की कर रहा था तैयारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा में सोमवार को एक युवक ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी दोनों शवों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसके भाई को घटना की जानकारी हुई और वह घर पहुंच गया। भाई के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान हीराधर यादव (60) और उनकी पत्नी गुलाबी यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर दोनों घर में मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर बेटे ने माता-पिता से विवाद किया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी के वार से सिर, गले और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शवों को बोरे में भर दिया और उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था।

भाई को पता चला तो घर पहुंचा,आरोपी भाग निकला : घटना की भनक आरोपी के भाई और गांव के लोगों को लगी। भाई तुरंत घर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। ग्रामीणों ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें दोनों के शव मिले। घर में जगह-जगह खून के छींटे भी पड़े थे। सूचना मिलते ही धौरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

मंगलवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे दिया गया। पुलिस ने डबल मर्डर का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है।

जनता ने फिर संभाली सड़क की जिम्मेदारी..गड्ढे में राहत की पैबंदकारी

गौरी पेट्रोल पंप-रावत रेजिडेंसी के पास एनएच-43 की बदहाली से परेशान थे राहगीर, नागरिकों की पहल पर हुई मरम्मत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

इसे व्यवस्था की विडंबना कहें या जनता की मजबूरी–जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना किसी चुनौती से कम न रह जाए तो आखिरकार नागरिकों को ही सड़क की सुध लेनी पड़ती है। अंबिकापुर-मनेन्द्रगढ़ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 पर गौरी पेट्रोल पंप से रावत रेजिडेंसी के पास लंबे समय से सड़क का एक हिस्सा इतना खराब हो गया था कि वह सड़क कम और टापू अधिक नजर आने लगा था। बारिश के दौरान स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। स्थानीय जागरूक नागरिक एवं रहवासी मुन्ना पांडेय ने इस समस्या को गंभीरता से उठाया। उनका कहना है कि खराब सड़क के कारण कारों के बंपर टूटने की नौबत आ रही थी, महिलाएं एक्टिवा से गिर रही थीं और ऑटो तक पलटने की स्थिति बन रही थी। ऐसे में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क कर तत्काल राहत की मांग रखी।

बारिश में सड़क नहीं,'रोमांचक सफर' : सड़क की स्थिति ऐसी थी कि वाहन चालक को गड्ढे से बचने के लिए सड़क पर नहीं, बल्कि मानो गड्ढों के बीच सड़क तलाशनी पड़ रही थी। बारिश का पानी भरने के बाद गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता था। दोपहिया वाहन चालकों और महिलाओं के लिए यह स्थिति विशेष रूप से जोखिम भरी बनी हुई थी। एनएच-43 की बदहाली कोई नई समस्या नहीं है। पूर्व में भी अंबिकापुर-मनेन्द्रगढ़ मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर शिकायतें और जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण सामने आ चुके हैं। अगस्त 2024 में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इसी मार्ग की खराब स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर जनसहयोग से गड्ढे भरने की पहल की थी।

नेताओं से चर्चा,फिर शुरू हुआ काम : मुन्ना पांडेय के अनुसार उन्होंने समस्या को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव,सरगुजा भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया एवं वींकी बाबा से चर्चा की। सभी ने जनहित में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की तत्परता से स्थानीय पार्षद कमलेश तिवारी एवं विनीत शुक्ला के साथ मिलकर उक्त स्थान पर सड़क की मरम्मत कराई गई। मरम्मत से फिलहाल राहगीरों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि खुद स्थानीय नागरिक भी मान रहे हैं कि बारिश के बीच यह स्थायी समाधान नहीं,बल्कि तत्काल राहत का प्रयास है। सड़क का व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण बारिश के बाद ही संभव होगा।

सवाल यह कि हर गड्ढे के लिए नागरिक ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सड़क की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी एजेंसियों की है,उसकी मरम्मत के लिए स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को आगे क्यों आना पड़ रहा है? अंबिकापुर की सड़कों की बदहाली को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2024 में एनएच-43 की खराब हालत के कारण दुर्घटनाओं और आवागमन में परेशानी की खबरें सामने आई थीं। इतना ही नहीं, वर्ष 2025 में एनएच-43 के पैचवर्क की गुणवत्ता को लेकर भी विवाद सामने आया और कार्रवाई की खबरें प्रकाशित हुईं। अब वर्ष 2026 में भी बारिश से पहले सड़क मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। जून 2026 में लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बारिश को देखते हुए सड़क रखरखाव और गड्ढों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे।

विकास की सड़क पर जनता की पैबंदकारी : *अंबिकापुर से जुड़े एनएच-43 के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की योजनाएं कागजों पर मौजूद हैं। 2026 में सूरजपुर-शिलफिली से अंबिकापुर के बीच एनएच-43 के 10.50 किमी हिस्से के सुदृढ़ीकरण के लिए निविदा प्रक्रिया भी हुई है। लेकिन योजनाओं और निविदाओं के बीच जब तक जमीन पर सड़क पूरी तरह दुरुस्त नहीं होती, तब तक सवाल राहगीरों की सुरक्षा का है। फिलहाल मुन्ना पांडेय और स्थानीय सहयोगियों की पहल से एक खराब हिस्से में राहत जरूर मिली है, लेकिन यह पहल व्यवस्था के लिए आईना भी है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक गड्ढे का नहीं है–सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?*

कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम भाजपा की सूची में,बोले...बिना प्रवेश बनाए पदाधिकारी

रवि नायक ने भाजपा को लिखित आपत्ति दी,सोशल मीडिया से सूची हटाई लेकिन भूल सुधार की सूचना नहीं देने का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता रविशंकर नायक का नाम भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की सूची में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। नायक वर्तमान में ग्राम करजी के कांग्रेस समर्थित उपसरपंच हैं। उनका आरोप है कि भाजपा में प्रवेश किए बिना ही उन्हें दरिमा मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा में मंत्री का पद दे दिया गया। मामले को लेकर उन्होंने भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों को लिखित आपत्ति भी दी है। नायक के अनुसार उन्हें एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि उनका नाम भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की दरिमा मंडल की सूची में शामिल है। सूची में अपना नाम और पद देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के करजी बूथ क्रमांक 169 में बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय हैं। पूर्व में वे ग्राम करजी के युवा मितान क्लब के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। रविशंकर नायक ने मामले को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र रवि और दरिमा मंडल अध्यक्ष को लिखित आपत्ति दी। इसके बाद भाजपा ने सोशल मीडिया से संबंधित सूची हटा दी, लेकिन सूची में हुई गड़बड़ी को लेकर सार्वजनिक रूप से भूल सुधार की सूचना जारी नहीं की गई। नायक का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सरगुजा जिला भाजपा अध्यक्ष से मई में मुलाकात कर भी जानकारी दी थी। वे मामले को स्पष्ट करने के लिए शपथपत्र देना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि शपथपत्र लेने से इनकार कर दिया गया। उन्हें गलती सुधारने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सुधार की स्थिति सार्वजनिक नहीं की गई है।

कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर उठाया सवाल : मामले को लेकर रविशंकर नायक ने कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी अनूप मेहता के साथ राजीव भवन में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा के छोटे-बड़े नेताओं से लेकर जिला अध्यक्ष तक से मामले में सुधार की मांग की,लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। नायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बिना भाजपा प्रवेश किए किसी व्यक्ति का नाम संगठन की सूची में शामिल किया जा सकता है तो यह भाजपा के संगठनात्मक कामकाज पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरगुजा में अपने संगठन की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के नाम का इस्तेमाल कर रही है।

होली क्रॉस स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, अम्बिकापुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हर्ष और उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके पश्चात विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। समारोह में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। 'तिरंगा भारत की शान' कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण शानदार प्रस्तुति दी। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समूहगान 'मेरा तिरंगा ऊंचा रहेगा' ने उपस्थित लोगों में देशभक्ति का भाव भर दिया। कक्षा 11वीं की छात्रा आराध्या जायसवाल ने ओजपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया और वर्तमान पीढ़ी को देशहित में समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पण और जिम्मेदारी की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में हिताक्षी दत्ता ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ शिक्षक सुनील कुमार तिवारी के नेतृत्व में देशभक्ति नारों के उद्घोष के साथ समारोह का समापन हुआ।

रायपुर में सरगुजा संभाग की छात्राओं ने दी देशभक्ति की शानदार प्रस्तुति...

राज्य स्तरीय समारोह में सरगुजा की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बढ़ाया गौरव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में सरगुजा संभाग की छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि से सरगुजा जिले एवं पूरे संभाग का गौरव बढ़ा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने आज कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात की। कलेक्टर वसंत ने छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके अनुशासन, मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा उन्हें भविष्य में भी इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा सहित शिक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर एवं शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर अम्बिकापुर की 286 छात्राओं ने सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व किया। छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से भारत की गौरवशाली स्वतंत्रता यात्रा, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता, विविधता और देश के प्रति समर्पण की भावना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रस्तुति में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने की गौरवपूर्ण भावना को भी शामिल किया गया।

भाग-2

सीईओ चंद्राकर की नई जांच पर बड़ा सवाल

'री-एंट्री' की रहस्यमयी तैयारी ?

35.78 लाख के फसल बीमा घोटाले में घोटालेबाजों को फिर बैंक में एंट्री देने की कवायद!

उठते बड़े सवाल

- नई जांच का आधार क्या है? नया सबूत क्या है?
- क्या पूर्व जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर त्रुटि सिद्ध हुई?
- क्या न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया?
- एफआईआर, विभागीय कार्रवाई और सेवा समाप्ति के समय बेगुनाही साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?
- क्या दोबारा जांच केवल 'री-एंट्री' का रास्ता बनाने के लिए?

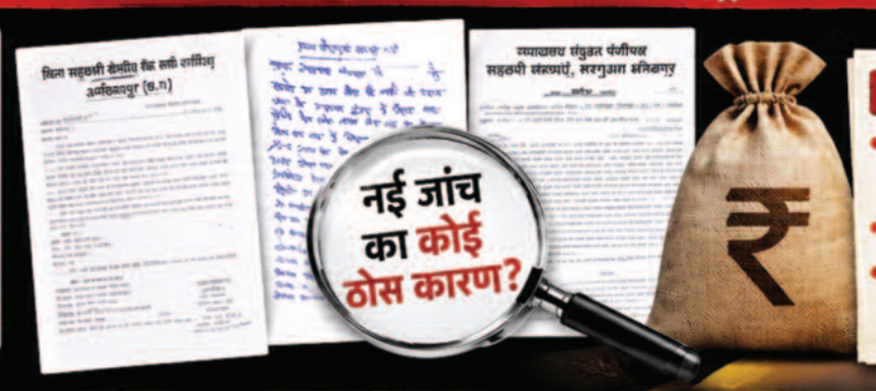

क्या यही है मकसद?

- पुरानी जांच के निष्कर्षों को कमजोर करना?
- जिम्मेदारों को बचाना?
- घोटालेबाजों की वापसी का रास्ता साफ करना?

क्या 35.78 लाख के घोटाले में फिर से 'री-एंट्री' की पटकथा लिखी जा रही है?

पहले जांच में दोषी,फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति...अब चुपके से 'री-एंट्री' की तैयारी? 35.78 लाख के फसल बीमा मामले में सीईओ चंद्राकर की नई कवायद

घोटालेबाजों की वापसी का रास्ता तैयार? 35.78 लाख के फसल बीमा मामले में सीईओ चंद्राकर की 'गुपचुप जांच' पर सवाल

- नई जांच से किसकी राह आसान होगी? 35.78 लाख के प्रकरण में जवाबदेही पर बड़े सवाल 'संरक्षण' के आरोपों का जवाब कौन देगा?
- नई जांच के पीछे किसकी कवायद? 35.78 लाख के प्रकरण में 'री-एंट्री' की तैयारी पर बड़े सवाल
- फसल बीमा घोटाले में 'री-एंट्री' का रास्ता! पहले जांच में दोषी,अब कनिष्ठ अधिकारियों से दोबारा जांच
- जिस जांच में दोषी पाए गए,उसी मामले में फिर जांच क्यों? फसल बीमा प्रकरण में सीईओ की कवायद पर सवाल

5 जून 2023 की कार्रवाई के बाद 23 जनवरी 2026 का आदेश,अब नई जांच से किसकी राह आसान होगी?

35.78 लाख के खेल में जांच पर जांच! पुराने दोषियों की वापसी की कवायद ने बढ़ाया रहस्य

पहले जिला प्रशासन की जांच,फिर बैंक की कार्रवाई...अब दोबारा जांच क्यों? फसल बीमा प्रकरण में उठे बड़े सवाल...

दोषी कौन,जांच कौन और फायदा किसे? 35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण में नई कवायद से सवाल...

सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

इस पूरे घटनाक्रम ने बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं–नियमित प्रक्रिया के तहत उसे अपना बचाव रखने का अवसर मिलना चाहिए,सवाल यह है कि क्या उस अवसर को देने के नाम पर 35.78 लाख रुपये के मूल प्रकरण की जांच फिर से उसी तरीके से की जा रही है,जिससे पहले की जांच और कार्रवाई का प्रभाव बदल जाए? यदि सीईओ के स्तर से नई जांच गठित की गई है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इसका लिखित आदेश क्या है? क्या कोई नया दस्तावेज सामने आया है? क्या पूर्व जांच में कोई प्रक्रियागत कमी पाई गई? क्या 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश में ऐसी कोई दिशा है जिसके अनुपालन के लिए जांच समिति आवश्यक है? क्या नई रिपोर्ट केवल बचाव का अवसर देने तक सीमित रहेगी या उसके आधार पर 5 जून 2023 के सेवा समाप्ति आदेश पर पुनर्विचार होगा? इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल : 35.78 लाख रुपये और किसानों का क्या हुआ?

इस प्रकरण का सबसे अहम पक्ष किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं,बल्कि किसानों की फसल बीमा राशि है,उपलब्ध दस्तावेजों में 35.78 लाख रुपये की राशि का उल्लेख है, 5 जून 2023 के बैंक आदेश में भी जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर इस राशि से संबंधित अनियमितता और चार कर्मचारियों की जवाबदेही का उल्लेख है,ऐसे में नई जांच का केंद्र भी सबसे पहले यह होना चाहिए कि किसानों की राशि का वास्तविक हिसाब क्या है, कितने किसानों के खातों से राशि का कथित फर्जी आहरण हुआ? प्रत्येक किसान के नाम पर कितनी राशि दर्ज थी? कुल 35.78 लाख रुपये में से कितनी राशि किस खाते या माध्यम से निकली? कितनी राशि की वसूली हुई? कितनी राशि अब भी लंबित है? क्या प्रभावित किसानों को उनकी राशि वापस की गई? क्या बैंक ने इस संबंध में ऑडिट या विशेष ऑडिट कराया? ये सवाल आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एफआईआर और विभागीय कार्रवाई के समय थे,यदि नई जांच इन मूल सवालों के जवाब तलाशने के बजाय केवल कर्मचारियों की सेवा बहाली के रास्ते तलाशती है, तो यह प्रक्रिया की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा।

दैनिक घटती-घटना ने पहले भी उठाया था मामला...

इस प्रकरण पर दैनिक घटती-घटना/कोरिया समाचार,सोमवार 09 मार्च 2026, पृष्ठ 6 पर 'सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। उसमें 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण,एफआईआर,निलंबन, सेवा समाप्ति और आगे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। यह सरकारी जांच दस्तावेज नहीं है,लेकिन इससे स्पष्ट है कि मामला पहले से सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा है, यदि अब नई जांच वास्तव में गठित की गई है तो बैंक या सहकारिता विभाग को यह भी बताना चाहिए कि पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर कोई आधिकारिक परीक्षण हुआ या नहीं।

क्या पुरानी जांच को नई रिपोर्ट से बदला जा सकता है?

यदि किसी जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई हुई और बाद में उसमें कमी पाई गई,तो उस कमी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्पष्ट किया जाना चाहिए। केवल नई समिति बनाकर पुराने निष्कर्षों के विपरीत रिपोर्ट आने से पहले की कार्रवाई अपने आप समाप्त नहीं हो जाती,नई जांच में पुराने निष्कर्ष सही पाए जाएं तो उन्हें बरकरार रखना होगा। यदि नए दस्तावेज से अलग तथ्य सामने आते हैं तो उसका स्रोत और प्रमाण रिकॉर्ड पर होना चाहिए। और यदि पुरानी जांच प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण थी तो उस त्रुटि की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

अब बैंक प्रबंधन से सीधे सवाल...

- **पहला सवाल**-नई जांच समिति गठित करने का लिखित आदेश कहां है और उसका क्रमांक क्या है?
- **दूसरा सवाल**-भैयाथान और सूरजपुर शाखा के शाखा प्रबंधकों को ही जांच की जिम्मेदारी देने का आधार क्या है?
- **तीसरा सवाल**-क्या नई जांच 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश के अनुपालन में है? यदि हां, तो आदेश के किस निर्देश के तहत?
- **चौथा सवाल**-क्या 5 जून 2023 के आदेश क्रमांक 383 में उल्लिखित जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को नई समिति पुनः जांचेगी?
- **पांचवां सवाल**-क्या कोई नया तथ्य, नया दस्तावेज या नई वित्तीय जानकारी सामने आई है?
- **छठा सवाल**-35.78 लाख रुपये की राशि में से अब तक कितनी वसूली हुई है और कितनी राशि शेष है?
- **सातवां सवाल**-क्या प्रभावित किसानों को राशि वापस की गई है? यदि हां,तो कितनी?
- **आठवां सवाल**-क्या नई जांच रिपोर्ट के आधार पर जगदीश प्रसाद कुशवाहा या अन्य संबंधित कर्मचारियों की सेवा में वापसी का प्रस्ताव है?
- **नौवां सवाल**-यदि ऐसा प्रस्ताव है तो उसका कानूनी और सेवा नियमों के तहत आधार क्या है?
- **दसवां सवाल**-क्या जांच समिति को किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र रूप से साक्ष्य जुटाने की अनुमति है या पहले से कोई निष्कर्ष तय किया गया है? इन सवालों के जवाब मिलने पर ही स्पष्ट होगा कि नई जांच वास्तव में न्यायालयीन आदेश की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद है या पुराने मामले में आरोपित कर्मचारियों की 'री-एंट्री' का रास्ता खोलने की कोशिश।

अब नजर बैंक प्रबंधन,सहकारिता विभाग और शासन के जवाब पर...

दैनिक घटती-घटना ने इस मामले को पहले भी प्रमुखता से उठाया था, 9 मार्च 2026 की 'सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?' रिपोर्ट में भी 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण,कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे,उस समय यह सवाल सामने आया था कि क्या कार्रवाई की दिशा बदलकर आरोपित कर्मचारियों के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है,अब नई जांच की कथित कवायद ने उसी सवाल को फिर सामने ला दिया है,अब कथित नई जांच की खबर सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है,बैंक प्रबंधन, सहकारिता विभाग और शासन के सामने पारदर्शिता के साथ यह बताने की जिम्मेदारी है कि 05.06.2023 के आदेश क्रमांक 383 और 23.01.2026 के प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023 के आदेश के बाद नई जांच की जरूरत क्यों पड़ी,यदि नई समिति बनाई गई है तो उसका आदेश सार्वजनिक किया जाना चाहिए,सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसी भी नई प्रक्रिया का केंद्र किसान और उनकी राशि होनी चाहिए। सेवा बहाली यदि नियमों के तहत संभव है तो वह भी पारदर्शी प्रक्रिया से हो, लेकिन 35.78 लाख रुपये के मूल प्रकरण की जवाबदेही और वसूली का सवाल उससे दबना नहीं चाहिए,जब तक इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आते,तब तक 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में नई जांच की कथित कवायद पर सवाल उठते रहेंगे। दस्तावेजों का क्रम यह बताता है कि मामला पहले ही कई स्तरों से गुजर चुका है। अब यदि फिर से जांच हो रही है तो किस आदेश के तहत, किस उद्देश्य से और किस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए,यह सार्वजनिक होना चाहिए,दैनिक घटती-घटना का सवाल सीधा है की यदि पुरानी जांच गलत थी तो उसे गलत साबित करने वाला नया दस्तावेज सामने लाया जाए,यदि प्रक्रिया अधूरी थी तो उसे नियमों के तहत पूरा किया जाए और यदि 35.78 लाख रुपये की अनियमितता के निष्कर्ष कायम हैं तो किसानों की राशि की वसूली और जिम्मेदारी तय करने को प्राथमिकता दी जाए,लेकिन चोरी-छिपे नई जांच, कथित गोपनीय निर्देश और किसी पक्ष के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराने की चर्चा,यदि सही है, तो यह सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल है। इसलिए बैंक प्रबंधन को आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए।

'संरक्षण' के आरोपों का जवाब कौन देगा?

इस पूरे घटनाक्रम ने बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं,सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं, नियमित प्रक्रिया के तहत उसे अपना बचाव रखने का अवसर मिलना चाहिए था जो उसे पूर्व में मिला भी पर अपने आपको कार्यवाही से बचा नहीं सके,जांच, एफआईआर और कार्रवाई के बाद अब फिर सवाल क्यों? जब 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में पहले ही विस्तृत जांच समिति गठित की गई थी और जांच के दौरान एक-एक साक्ष्य,दस्तावेज और वित्तीय अनियमितता को जांच प्रतिवेदन में दर्ज किया गया था,तभी मामला एफआईआर तक पहुंचा और आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की स्थिति बनी, यदि उस समय संबंधित लोगों को लगता था कि वे दोषी नहीं हैं अथवा जांच में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्हें उसी समय अपनी बेगुनाही के पक्ष में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने और जांच के निष्कर्षों को चुनौती देने का पूरा अवसर था, अब सवाल यह है कि वर्षों बाद अचानक ऐसी कौन-सी नई परिस्थिति या नया साक्ष्य सामने आ गया है, जिसके आधार पर पहले से जांचे और कार्रवाई किए जा चुके प्रकरण को फिर से जांच के लिए खोला जा रहा है? क्या पूर्व जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर त्रुटि साबित हुई है? क्या उस जांच को सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त किया है? या फिर संबंधित आरोपितों को न्यायालय ने इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है? यदि न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है और पूर्व जांच रिपोर्ट को भी विधिवत निरस्त नहीं किया गया है, तो फिर नई जांच का औचित्य क्या है? क्या केवल दोबारा जांच कर लेने से पहले की जांच में दर्ज निष्कर्ष और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? सबसे अहम सवाल यही है कि जिस समय एफआईआर हुई, विभागीय कार्रवाई हुई और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई पहुंची, उस समय अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?

अब यदि नई जांच हो रही है, तो बैंक प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि नई जांच का आधार क्या है, नया साक्ष्य क्या है और क्या किसी न्यायालय ने संबंधित आरोपितों को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया है? वरना यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं पुरानी जांच के निष्कर्षों को बदलकर फिर से 'री-एंट्री' का रास्ता तो तैयार नहीं किया जा रहा?

भारतीय व्यापार महोत्सव में छत्तीसगढ़ के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित महोत्सव में एमसीबी सहित छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की गरिमामयी सहभागिता

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा देने तथा देशभर के व्यापारियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 14 एवं 15 अगस्त को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया, राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से जुड़े व्यापारियों एवं प्रतिनिधियों ने सहभागिता की,महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी, उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए, इस दौरान व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार,आधुनिक तकनीक के उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म,ई-कॉमर्स तथा नए बाजारों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया, भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य देश के व्यापारिक समुदाय को एक सशक्त राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना,स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए नए

कारोबारी अवसर उपलब्ध कराना रहा, आयोजन में डिजिटल भुगतान,लॉजिस्टिक्स,नवाचार,ई-कॉमर्स और बदलते कारोबारी परिवेश जैसे विषयों पर भी विशेष चर्चा हुई, व्यापारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर आपसी सहयोग और व्यापार विस्तार की संभावनाओं पर विचार साझा किए।

एमसीबी सहित छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी-अमर परवानी के नेतृत्व में रघुनाथ पोद्दार,रफीक मेमन, शोएब अख्तर,मनीष अग्रहरि,प्रमोद सिंह,रवि गुप्ता,मोहम्मद सिराज,संदीप दुआ,कृति सोनी,माखन जायसवाल,अरविंद सराफ सहित अन्य व्यापारिक प्रतिनिधियों ने महोत्सव में छत्तीसगढ़ की सहभागिता दर्ज कराई,प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन व्यापारियों को देश के बदलते कारोबारी परिवेश को समझने,नई तकनीकों से परिचित होने और विभिन्न राज्यों के व्यापारिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर देते हैं, खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ऐसे मंच नए बाजारों तक पहुंच बनाने और व्यापार को व्यापक स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं,प्रतिनिधियों ने महोत्सव के दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं उद्यमियों से संवाद करते हुए छत्तीसगढ़ में व्यापार की संभावनाओं, स्थानीय उत्पादों, बाजार विस्तार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी चर्चा की।

CMYK

एमसीबी कलेक्टर कार्यालय के भूमिपूजन को लेकर मंत्री और पूर्व विधायक आमने-सामने

गुलाब कमरो का पलटवार...स्वास्थ्य मंत्री जी...चश्मे की जरूरत आपको है,मुझे नहीं...कार्यालय की जगह,प्रोटोकॉल और जिले के संघर्ष को लेकर सियासत तेज

खबर विशेष

मनेंद्रगढ़,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के भूमिपूजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है,भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों,जनप्रतिनिधियों की कथित उपेक्षा और कलेक्टर कार्यालय के लिए चयनित स्थान को लेकर सवाल खड़े किए हैं, दोनों नेताओं के बयानों के बाद कलेक्टर कार्यालय का भूमिपूजन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आरोप लगाया कि कलेक्टर कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ आनन-फानन में किया गया,उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए न तो उचित प्रोटोकॉल तैयार किया गया,न आमंत्रण पत्र जारी किए गए और न ही क्षेत्र के सांसद, जनप्रतिनिधियों तथा उन लोगों को आमंत्रित किया गया,जिन्होंने एमसीबी जिले के निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया,आंदोलन किए और जेल तक गए।

कलेक्टर कार्यालय की जगह को लेकर सवाल...

गुलाब कमरो ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग और जनभावनाओं को देखते हुए कई बार पत्र लिखकर कलेक्टर कार्यालय ऐसी जगह बनाए जाने की मांग की थी,जो जनकपुर, कोटाडोल और भरतपुर जैसे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए सुगम हो तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित हो, उनका कहना है कि इसके बावजूद जनभावनाओं और सुझावों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में स्थान तय किया गया,उन्होंने सवाल उठाया कि जब पर्याप्त तैयारी नहीं थी,जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हुई और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं की गई तो निर्माण कार्य के शुभारंभ में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई?

चश्मे की जरूरत आपको है,मुझे नहीं...

मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा...'स्वास्थ्य मंत्री जी, चश्मे की जरूरत आपको है, मुझे नहीं,' उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने एमसीबी जिले का निर्माण नहीं किया होता तो आज भाजपा सरकार और मंत्री को कलेक्टर कार्यालय के भूमिपूजन का श्रेय लेने का अवसर ही नहीं मिलता,कमरो ने भाजपा सरकार के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जब प्रदेश में लंबे समय तक भाजपा की सरकार थी और मंत्री स्वयं विधायक रहे, तब एमसीबी जिला क्यों नहीं बनाया गया और उस दौरान कलेक्टर कार्यालय का भूमिपूजन क्यों नहीं हुआ?

सड़कों के श्रेय पर भी राजनीतिक वार

पूर्व विधायक ने भरतपुर क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों के श्रेय को लेकर भी मंत्री पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में गिना रही है,उनमें क्षेत्र की सांसद और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के प्रयासों की भी भूमिका है,उन्होंने कहा कि'जनता सब देख रही है–जिला कांग्रेस सरकार ने बनाया,सड़कें सांसद के प्रयासों से आ रही हैं और अब श्रेय लेने भाजपा मैदान में उतर गई है। '

मंत्री ने मंच से दिया जवाब...

भूमिपूजन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने उन्हें केवल कलेक्टर और एसपी दिए थे,'बाबू भी नहीं मिले थे,'कलेक्टर कार्यालय के स्थान को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जनकपुर और कोटाडोल से लोग पांच किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं,मंत्री ने कहा कि हाईवे पर जिला पंचायत कार्यालय का निर्माण हो रहा है और जहां जमीन उपलब्ध हुई है,वहां कलेक्टर,एसपी,खनिज और परिवहन विभाग के कार्यालय बनाए जाएंगे,उन्होंने विकास कार्यों पर सवाल उठाने वालों से 'पावर वाला चश्मा'लगाने की बात कही,भरतपुर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने करीब एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य होने का दावा भी किया और कहा कि विकास कार्यों का विरोध करने के बजाय उसमें सहयोग किया जाना चाहिए।

दूरस्थ ग्रामीणों की परेशानी का मुद्दा...

मंत्री के इस बयान पर भी कमरो ने आपत्ति जताई कि जनकपुर और कोटाडोल से लोग पांच किलोमीटर और आगे जा सकते हैं,उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है,साधन-विहीन ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त दूरी तय करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप ऐसे बयानों से बचना चाहिए,गुलाब कमरो ने कहा कि एमसीबी जिला केवल प्रशासनिक इकाई नहीं,बल्कि क्षेत्र की जनता के लंबे संघर्ष और जनभावनाओं का परिणाम है,इसलिए जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण जैसे ऐतिहासिक अवसरों पर संघर्ष करने वाले लोगों,जनप्रतिनिधियों और जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए,उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों का विरोध उनका उद्देश्य नहीं है,लेकिन विकास के साथ पारदर्शिता,लोकतांत्रिक परंपराओं और क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों का सम्मान भी जरूरी है।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिले भाजपा युवा नेता राहुल खटीक,कोरिया में फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की मांग

बैकुंठपुर-कोरिया में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने को लेकर हुई चर्चा

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा युवा नेता राहुल खटीक ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं अभिनेता चिराग पासवान से मुलाकात कर कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा कृषि आधारित रोजगार सुविधाओं की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की,इस दौरान क्षेत्र की कृषि क्षमता, स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने से जुड़े विषयों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। राहुल खटीक ने केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए आवेदन में बताया कि कोरिया जिला कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है,जिले के किसान कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों पर काफी हद तक निर्भर हैं,क्षेत्र में धान,मक्का,दलहन,फल-सब्जियों सहित विभिन्न स्थानीय कृषि एवं वनोपज का उत्पादन होता है,लेकिन पर्याप्त प्रसंस्करण, भंडारण और बेहतर बाजार व्यवस्था के अभाव में किसानों को अपनी उपज का अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता,उन्होंने कहा कि यदि जिले में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाती है तो कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के साथ उनका स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किया जा सकेगा, इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और फसल खराब होने की समस्या में भी कमी आएगी।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिनी प्रोसेसिंग सेंटर की मांग-केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोरिया जिले में आधुनिक Food Processing Unit,Cold Storage एवं Warehouse स्थापित करने की मांग रखी गई, इसके साथ ही कोदो-कुटकी,मक्का, दलहन तथा अन्य स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए Mini Processing Center स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया,आवेदन में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं के विशेष शिविर आयोजित कर ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की बात भी रखी गई।

पैकेजिंग,ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर-राहुल खटीक ने किसानों के लिए पैकेजिंग,ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की सुविधाएं विकसित करने तथा कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई,उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए तो इससे किसानों के साथ-साथ स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को भी आर्थिक लाभ मिल सकता है,इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों को विशेष आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी गई, ताकि किसान सामूहिक रूप से उत्पादन,प्रसंस्करण और विपणन की गतिविधियों से जुड़ सकें।

रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद-राहुल खटीक ने कहा कि कोरिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित होने से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने क्षेत्र में ही काम के अवसर मिल सकेंगे,उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर-कोरिया क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जरूरत इन संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की है,केंद्रीय मंत्री के समक्ष क्षेत्र की मांगों को प्रमुखता से रखा गया है और उम्मीद है कि इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी,उन्होंने कहा कि कोरिया के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर मंथन

लंबित मांगों की समीक्षा,नए ज्ञापन और गंभीर मामलों में PIL दायर करने की बनी रणनीति

-संवाददाता-

कोरिया/सोनहत,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक आनंदपुर-कटगोड़ी स्थित नर्सरी परिसर में आयोजित की गई, बैठक में क्षेत्र की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं,नागरिक सुविधाओं,अधूरे विकास कार्यों,ग्रामीणों की समस्याओं और जनहित से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से मंथन किया गया, समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास,आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास करना समिति की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान समिति द्वारा पूर्व में शासन-प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापनों एवं मांग पत्रों की समीक्षा की गई, सदस्यों ने लंबित मांगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं,इन मामलों को लेकर आगामी दिनों में संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों से पुनः संपर्क कर ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी,समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि कोरिया जन सहयोग समिति लगातार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है,स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समिति ने यह संकल्प दोहराया है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा,उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जनता की जायज मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाता है तो समिति लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन से लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई तक का रास्ता अपनाएगी, समिति के सचिव राजू साहू ने कहा कि पूर्व में सौंपे गए कई महत्वपूर्ण ज्ञापनों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है,समिति ने निष्पादित और लंबित मामलों की सूची तैयार की है तथा लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए शासन-प्रशासन का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाएगा।

वन क्षेत्र के निर्माण कार्यों की जांच की मांग-बैठक में वन विभाग तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया,सदस्यों ने इन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, समिति का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सेमरिया पुलिया और अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा-सेमरिया में लंबे समय से जर्जर एवं टूटी पुलिया के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर भी बैठक में चर्चा हुई,सदस्यों ने कहा कि पुलिया की स्थिति से आवागमन प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, समिति ने पुलिया का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की,इसी तरह चंदाहा-बंशीपुर-कचोहर क्षेत्र में अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया गया, ग्रामीणों को जल्द बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए समिति ने संबंधित विभाग से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई, सोनहत के धुम्माडाण्ड क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या और जर्जर सड़कों की मरम्मत का विषय भी बैठक में प्रमुखता से रखा गया,इसके अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों में लंबित निर्माण एवं जनसुविधा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने, वन क्षेत्र से लगे ग्रामीणों के अधिकार,मुआवजा, मानव-वन्यजीव संघर्ष और स्थानीय निवासियों से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

प्रशासनिक कार्रवाई के साथ विधिक रास्ते पर भी जोर-बैठक में उपस्थित विधिक सलाहकारों ने जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन दिया, अधिवक्ता रज़ा अली अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं और मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना नागरिकों का अधिकार है,यदि पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनहित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष भी रखा जा सकता है,अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक और विधिक दोनों स्तरों पर मजबूती से प्रयास आवश्यक है, जिन मामलों में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनमें उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी रणनीति तैयार की जाएगी।

नए ज्ञापन के साथ पीआईएल की तैयारी-बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेमरिया पुलिया,अधूरा विद्युती करण,सोनहत क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं सहित अन्य लंबित जनहित के मुद्दों को लेकर जल्द ही सक्षम अधिकारियों से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, वहीं वन विभाग तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं जैसे गंभीर मामलों में आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यों का संकलन कर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया, समिति का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य मामलों की निष्पक्ष जांच और जनहित में उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराना होगा, समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित दस्तावेजों, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

अधिवक्ताओं और सदस्यों की मौजूदगी-बैठक में विधिक सलाहकार अधिवक्ता रज़ा अली अंसारी,अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर,अधिवक्ता अरविंद सिंह एवं अधिवक्ता शहज़ाद अंसारी उपस्थित रहे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े,सचिव राजू साहू,राजन पाण्डेय, नीलेश सोनी,एहसानुल हक,प्रफुल्ल पाण्डेय, बालकरण सोनपाकर सहित समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे,बैठक के समापन पर समिति ने क्षेत्रीय जनता के अधिकारों, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

अग्रवाल महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया सावन उत्सव

सावन सुंदरी प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र,आयुषी तायल चुनी गईं सावन सुंदरी 2026

-संवाददाता-

सूरजपुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अग्रवाल महिला मंडल द्वारा अग्रोहा भवन में सावन उत्सव का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया, सावन की उमंग और उत्साह से सराबोर कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया,पूरे आयोजन के दौरान हंसी-खुशी, आपसी सौहार्द और मनोरंजन का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में महिलाओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स, हाउजी और लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,आयोजन का मुख्य आकर्षण सावन सुंदरी प्रतियोगिता रही,प्रतियोगिता में तीन वर्ष से अधिक समय से विवाहित महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा एवं आकर्षक अंदाज का प्रदर्शन किया।

आयुषी तायल बनीं सावन सुंदरी 2026-सावन सुंदरी प्रतियोगिता में आयुषी तायल को सावन सुंदरी 2026 चुना गया, वहीं मनमोहक सावन सुंदरी का द्वितीय पुरस्कार चंचल गोयल को तथा सावन सुंदरी का तृतीय पुरस्कार सजल अग्रवाल को प्रदान किया गया, मनोहर सावन सुंदरी का पुरस्कार लहर मित्तल ने प्राप्त किया, इसके अलावा चारू अग्रवाल एवं विधि पालीवाल को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया, प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई, प्रतिभागियों के उत्साह और आयोजन की आकर्षक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया।

खान-पान के स्टॉल और झूलों का उठाया आनंद-सावन उत्सव में विभिन्न प्रकार के खान-पान के स्टॉल भी लगाए गए थे, महिलाओं और बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया,इसके साथ ही परिसर में लगाए गए झूलों का भी बच्चों और महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया, आयोजन स्थल पर सावन के अनुरूप सजावट और गतिविधियों ने उत्सव के माहौल को और खुशनुमा बना दिया।

सदस्यों के सहयोग से सफल हुआ आयोजन-कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रवाल महिला मंडल की सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा,ममता अग्रवाल,सीमा गर्ग, रिंकी अग्रवाल,लता गोयल,सुमन गोयल, पूजा अग्रवाल,आशा अग्रवाल,सीमा अग्रवाल, काजल अग्रवाल,मीना गोयल,मंजू गोयल, विजया गर्ग,गीता अग्रवाल,रेखा गोयल,कुसुम अग्रवाल,नीता गोयल,उषा अग्रवाल,पिंकी केजरीवाल एवं विधि अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई,अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष ममता अग्रवाल ने आयोजन की सफलता पर सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और आपसी सामंजस्य से सावन उत्सव को यादगार बनाने में सफलता मिली,ऐसे आयोजन महिलाओं को एक-दूसरे से जुड़ने,अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और मिल-जुलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते हैं, उन्होंने कहा कि आयोजन की सफलता प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

CMYK

शाहिद कपूर का शर्टलेस अवतारः इटली में मीरा संग बिता रहे छुट्टियां

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा कपूर के साथ इटली में गर्मियों का मज़ा ले रहे हैं। दोनों ने लेक कोमो में एक खूबसूरत ट्रिप का आनंद लिया। मीरा ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर कीं,जिनमें वे इटली की झील में बोट की सवारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में शाहिद बिना शर्ट के मीरा के साथ बोट पर पोज़ देते हुए दिख रहे हैं। सनग्लासेस और चेन पहने हुए एक्टर मुस्कुरा रहे हैं और दोनों लेक कोमो के शानदार नज़ारे के सामने पोज़ दे रहे हैं। वहीं,मीरा ब्राउन आउटफिट में शाहिद के बगल में बैठी हुई दिख रही हैं। इन तस्वीरों में मीरा को बोट पर धूप का मज़ा लेते हुए और लेक कोमो के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए भी दिखाया गया है। तस्वीरें शेयर करते हुए मीरा ने छोटा और इटैलियन अंदाज़ वाला कैप्शन लिखा,ला डोलसे वीटा की ज़रूरी चीज़ें। यह छुट्टी मीरा की उस इच्छा के भी अनुरूप है जो उन्होंने पहले ज़ाहिर की थी कि वे छुट्टियों के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हैं।
इससे पहले, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया था कि वे सोशल मीडिया के लगातार शोर-शराबे और हमेशा अच्छे दिखने के दबाव से दूर रहना चाहती हैं और अपनी छुट्टियों के दौरान बस आराम से, आज़ाद और वर्तमान पल में जीना चाहती हैं। मीरा ने लिखा था, ब्रेन डंप मैं ये हॉलिडे लुक्स नहीं कर सकती। अब इंस्टाग्राम के लिए आउटफिट्स का दबाव नहीं चाहिए,कि ये इसके साथ मैच करे या वो उसके साथ। इतने सालों तक मुझे यह सब पसंद था,लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उन्होंने आगे कहा,जब मैं इतने सारे विकल्पों के बीच उलझी हुई हूँ,तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरा मन अब भर गया है। मैं गर्मियों में आराम करने और ट्रैक पैंट और पोनीटेल में अपने बच्चों और अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं अच्छे मूड में कोई पोस्ट करती हूँ और उसमें मेरे आउटफिट्स कुछ खास नहीं होते, तो उन्हें नज़रअंदाज़ करने के लिए पहले से ही धन्यवाद। तब तक के लिए।

ओटीटी पर गदर काटने आ रही द रिवोल्यूशनरीज, किरदारों से उठा पर्दा,रिलीज डेट का हुआ ऐलान

डायरेक्टर निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा उन चार भूले-बिसरे हीरोज की कहानी देखने को मिलेगी, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीरीज में रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, भुवन बाम और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे।
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों देशभक्ति और देशप्रेम के जुनून से भरी बटवारा 1947 का जलवा देखने को मिल रहा है। सनी देओल स्टारर बटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस बीच अमेजन प्राइम वीडियो ने एक नई सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें चार ऐसे भूले-बिसरे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी देखने को मिलेगी,जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। मेकर्स ने हाल ही में इस नई सीरीज के किरदारों से पर्दा उठाया है और साथ ही साथ इसकी स्ट्रीमिंग डेट का भी ऐलान कर दिया है

द रिवोल्यूशनरीज की रिलीज डेट का ऐलान

प्राइम वीडियो ने इस साल की शुरुआत में द रिवोल्यूशनरीज का ऐलान किया था, जो अब

बहुत जल्द ओटीटी पर धमाके के लिए तैयार है। ये सीरीज 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर में स्ट्रीम होगी। मशहूर फिल्ममेकर निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी ये हाई-ऑक्टेन पीरियड ड्रामा सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित और आजादी की लड़ाई की अनसुनी कहानी है। ये सीरीज संजीव सान्याल की बेस्टसेलर किताब रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पर आधारित है।

द रिवोल्यूशनरीज की स्टारकास्ट

इस सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सीरीज में जैसन शाह, पाओली दम और तोता रॉय चौधरी भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। सीरीज का प्रीमियर 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर हिंदी में होगा। हालांकि,इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,बंगाली में डब और अंग्रेजी सहित कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स मिलेंगे और इसे भारत और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में देखा जा सकेगा।

फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी है सीरीज

द रिवोल्यूशनरीज भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी है, जिसमें भुवन बाम (रास बिहारी बोस), रोहित सराफ (सचिंद्र नाथ सान्याल), प्रतिभा रांटा (प्रतिभा लाहिरी) और गुरफतेह पीरजादा (बाघा जतिन) की भूमिका में नजर आएंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जन्मे ये युवा रिवोल्यूशनरीज जस्टिस, लिबर्टी और आजादी के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं और देश की आजादी की खातिर आर्म्ड रेजिस्टेंस के खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इस सीरीज में इन चार फ्रीडम फाइटर्स की हिम्मत, बलिदान, दोस्ती, धोखे और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइसेज देखने को मिलेंगे, जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के एक अहम चैप्टर को शेप देने में मदद की।

महिला किरदारों पर तापसीः जटिलता मिलने से दिलचस्प होता है सिनेमा

एक्ट्रेस तापसी पन्नू,जो फिल्म फेस्टिवल के 14वें एडिशन में एक पैनल डिस्कशन में शामिल होने वाली हैं,ने कहा है कि सिनेमा तब दिलचस्प हो जाता है जब महिला किरदारों को कमियों वाला,उलझा हुआ और बिना किसी झिझक के खुद जैसा दिखाया जाता है। एक्ट्रेस जागरण फिल्म फेस्टिवल में 'फ्रॉम पिंक टू पावरः ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स थ्रू सिनेमा' पैनल में शामिल होंगी,जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल सिनेमा की उस ताकत का जश्न मनाता है जो नज़रिए को चुनौती देती है। बातचीत शुरू करती है और बदलती दुनिया को दिखाती है। साथ ही, यह भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे दमदार आवाज़ों को एक साथ लाता है। इस खास सेशन के बारे में बात करते हुए तापसी पन्नू ने एक बयान में कहा...मेरे लिए,स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की शुरुआत हमेशा रिस्क लेने और ऐसी महिला का किरदार निभाने से हुई है जो शायद लोगों की उम्मीदों के मुताबिक न हो।इस सेशन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे सिनेमा गहरी जड़ें जमा चुके स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठा सकता है,स्क्रीन पर महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके को बदल सकता है और दर्शकों को जानी-पहचानी कहानियों से हटकर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। तापसी अपने सफर,अपने करियर को आकार देने वाले फैसलों, पारंपरिक ढर्रे से हटकर काम करने में आने वाले रिस्क और सिनेमा का इस्तेमाल सवाल उठाने, सोचने पर मजबूर करने और प्रेरित करने के लिए करने की ज़िम्मेदारी पर बात करेंगी। उन्होंने आगे कहा,पिंक और थप्पड़ जैसी फिल्में एक बड़ी बातचीत का हिस्सा बनीं क्योंकि उनके किरदार सिर्फ़ किसी जाने-पहचाने ढर्रे में फिट होने के लिए नहीं बनाए गए थे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सिनेमा तब और दिलचस्प हो जाता है जब हम महिलाओं को कमियों वाला,उलझा हुआ,महत्वाकांक्षी और बिना किसी झिझक के खुद जैसा होने देते हैं। मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल में इन फैसलों और उनसे शुरू हुई बातचीत पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हूं। फिल्म फेस्टिवल 20 अगस्त से 23 अगस्त, 2026 तक नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है।

सैफ अली खान और कियारा आडवाणी पहली बार साथ आएंगे नजर

बॉलीवुड के दो बड़े सितारे सैफ अली खान और कियारा आडवाणी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। दोनों कलाकार एक सुपरनैचुरल एलिमेंट वाली थ्रिलर फिल्म में काम करेंगे,जिसे राइटर-प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों डायरेक्ट करने जा रही हैं। यह फिल्म कनिका ढिल्लों के निर्देशन करियर की पहली फिल्म होगी। फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं किया गया है। हालांकि,इस प्रोजेक्ट को लेकर बॉलीवुड में चर्चा तेज हो गई है। फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसे एक अलग तरह की कहानी के रूप में तैयार किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक,फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है। मेकर्स कहानी को सैफ अली खान और कियारा आडवाणी को ध्यान में रखकर तैयार कर रहे हैं। फिल्म में थ्रिल, रहस्य और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र के अनुसार,सैफ और कियारा कनिका ढिल्लों की इस फिल्म में पहली बार साथ काम करेंगे। यह एक दमदार थ्रिलर होगी, जिसमें अलौकिक घटनाओं को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। सूत्र ने बताया कि कनिका ढिल्लों, एक्सेल एंटरटेनमेंट और राइटिंग टीम काफी समय से इस कहानी पर काम कर रहे हैं। अब मेकर्स इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू होने की संभावना है। सैफ अली खान बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जो लगातार अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ प्रयोग करते रहे हैं। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से लेकर क्राइम थ्रिलर और गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता दिखाई है।

वहीं,कियारा आडवाणी भी पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना चुकी हैं। उन्होंने रोमांटिक,कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। अब सुपरनैचुरल थ्रिलर जैसे जॉनर में उनका नया अंदाज देखने को मिलेगा। कनिका ढिल्लों की बात करें तो वह बॉलीवुड की चर्चित लेखिकाओं में शामिल हैं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी और स्क्रीनप्ले लिखे हैं। अब वह पहली बार निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। ऐसे में उनकी पहली फिल्म को लेकर दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में उत्सुकता बढ़ गई है।

सुपरनैचुरल थ्रिलर जॉनर बॉलीवुड में हमेशा से दर्शकों को आकर्षित करता रहा है। इस तरह की फिल्मों में रहस्य, डर और रोमांच का मेल देखने को मिलता है। मेकर्स इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एक नया अनुभव देने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट भी अलग तरह के कंटेंट के लिए जाना जाता है। प्रोडक्शन हाउस ने इससे पहले कई सफल और चर्चित फिल्मों का निर्माण किया है। अब सैफ और कियारा की जोड़ी के साथ यह एक नए जॉनर की फिल्म लेकर आने जा रहा है। फिल्म की कहानी और बाकी कलाकारों को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। मेकर्स ने भी आधिकारिक तौर पर फिल्म की पूरी घोषणा नहीं की है। हालांकि, फिल्म से जुड़े अपडेट का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। सैफ और कियारा की नई जोड़ी बॉलीवुड के लिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि दोनों कलाकारों ने अब तक अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है। पहली बार दोनों को स्क्रीन शेयर करते देखना दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। फिलहाल फिल्म की तैयारी शुरुआती चरण में है और आने वाले समय में इसके टाइटल,शूटिंग शेड्यूल और बाकी कलाकारों से जुड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

एक्टर शाहरुख खान के मन्नत में घुसा 8 फीट लंबा सांप

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का मुंबई स्थित बंगला मन्नत एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल,उनके बंगले में दो सांप दिखाई दिए। सांप नजर आते ही बंगले के सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी सावधानी के बाद एक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक,सांप को सबसे पहले बंगले के गार्ड ने देखा था। उसे देखते ही सुरक्षा को लेकर तुरंत वन विभाग को फोन किया गया। इस पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ सांप रेस्क्यू करने वाले विक्की दुबे भी मन्नत पहुंचे। टीम ने पूरे परिसर में तलाशी ली। इस दौरान एक सांप बंगले के गार्डन में बने शेड के अंदर छिपा हुआ मिला।
विक्की दुबे ने सांप को सावधानी से बाहर निकाला और बताया कि यह करीब आठ फीट लंबा धामण नस्ल का सांप है। धामण को इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है और यह सांप जहरीला नहीं होता। हालांकि, रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम की पकड़ में आने से पहले ही दूसरा सांप वहां से निकल गया। उसे पकड़ने के लिए काफी देर तक तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। वन विभाग की ओर से यह माना गया कि दूसरा सांप संभवत बंगले के परिसर से बाहर निकल गया होगा। बता दें कि मन्नत में इस समय मरम्मत का काम भी चल रहा है। इसी वजह से शाहरुख खान फिलहाल अपने परिवार के साथ बंगले में नहीं रह रहे हैं। वह बांद्रा के एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। मुंबई में फिल्मी सितारों के घरों में सांप पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी सांप दिखाई दिया था। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाकर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया था।

खेल समाचार

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का ऐलान तेजस्विन और दिव्या देशमुख को अर्जुन पुरस्कार

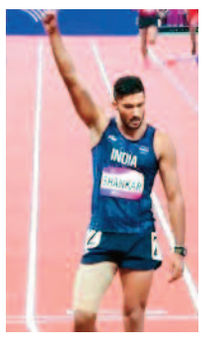

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की घोषणा की है,जिसमें एथलीट तेजस्विन शंकर,शतरंज के सितारे विदित गुजराती,दिव्या देशमुख और बैडमिंटन जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली को अर्जुन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर,सरकार ने निम्नलिखित खिलाड़ियों,प्रशिक्षकों और संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना जैसे गुणों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले एथलीट हैं- तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स),मुहम्मद अजमल वरियाथोडी (एथलेटिक्स),प्रियंका गोस्वामी (एथ लेटिक्स),ट्रीसा जॉली (बैडमिंटन),गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन),नरेंद्र (मुक्केबाजी), विदित संतोष गुजराती (शतरंज) दिव्या जितेंद्र देशमुख (शतरंज),धनुष श्रीकांत (बधिर शूटिंग),लालरेम्सियामी (हॉकी),राजकुमार पाल (हॉकी),सुरजीत (कबड्डी),पूजा (कबड्डी),रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भ्याण (पैरा-शूटिंग),अरविंद सिंह (रोइंग) और अखिल श्योराण (शूटिंग)। खेल और खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2025 में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार (आजीवन) उन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कोच अरुमैनायगम (फुटबॉल) को यह पुरस्कार प्राप्त होगा।खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाएगा जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। नियमित वर्ग में पुरस्कार पाने वालों में परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग) और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) शामिल होंगे, जबकि धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग) और वीरेंद्र कुमार (कुश्ती) को लाइफटाइम सम्मान से नवाजा जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच एफ आईएच हॉकी विश्व कप का एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा

एमस्टेलवीन,18 अगस्त 2026। विश्व हॉकी में कुछ ही मुकाबले भारत-पाकिस्तान मुकाबले जितना महत्व और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और बुधवार को एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में जब ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने होंगे तो वैसा ही रोमांच देखने को मिलेगा। हॉकी इंडिया की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वैगनर हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह तनावपूर्ण मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में कौन बना रहेगा, क्योंकि पूल डी के इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान हॉकी की सबसे ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता में से एक को फिर से दोहराएंगे, यह जानते हुए कि गलती की गुंजाइश बहुत कम है।

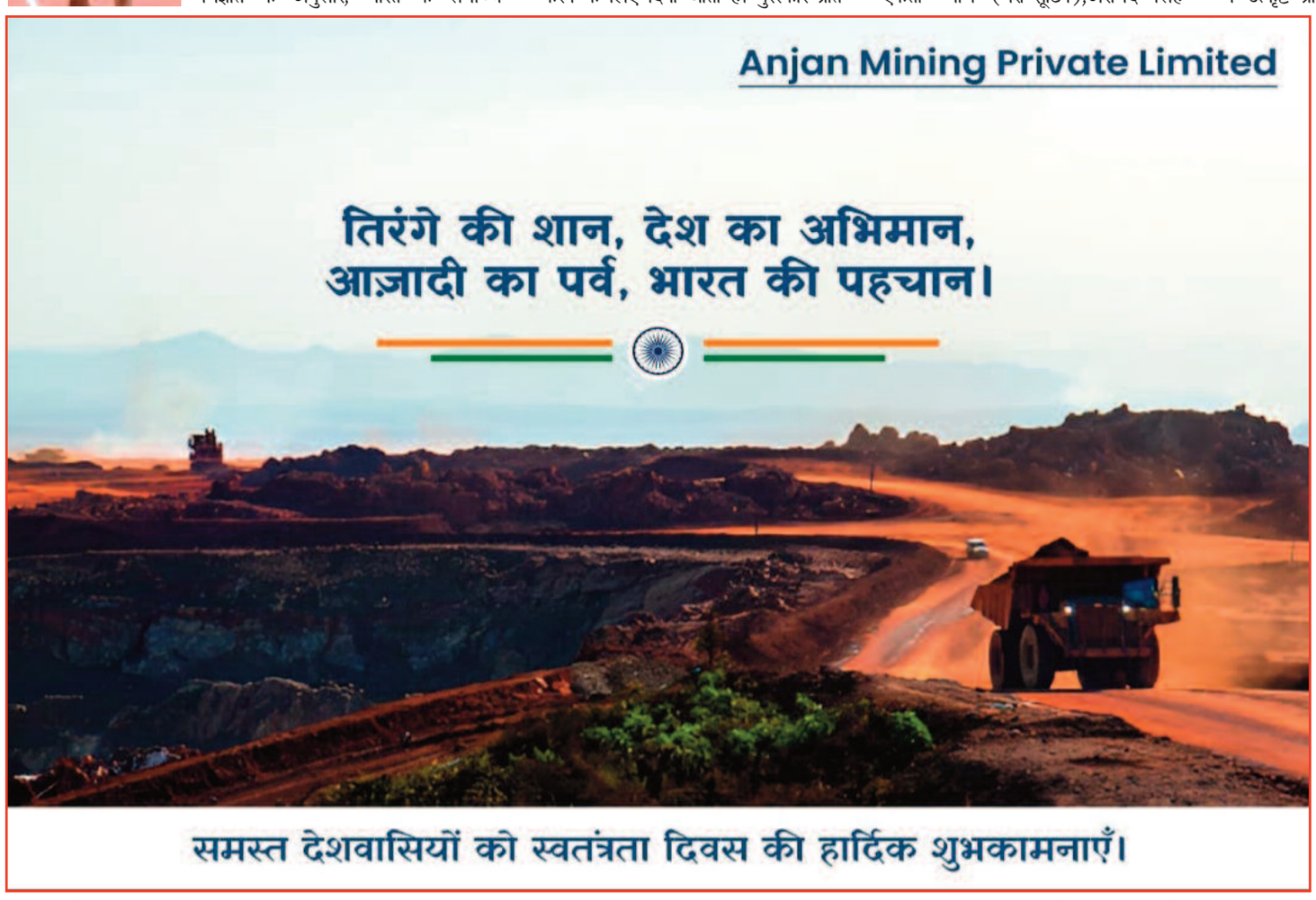

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क... /20/1//2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका विजय कुमार चौबे आ0/पति स्व0 छत्रधारी चौबे जाति निवासी सत्तीपारा,अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर - 2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 621/17 रकबा 0.018 हे0 भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/ आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 21.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।
आज दिनांकः- 04.08, 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क... /20/1//2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका रूकमणी चौबे आ0/ पति विजय कुमार चौबे जाति निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला--सत्तीपारा, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3385/9 रकबा 915 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है
अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।
आज दिनांक- 11.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी अंबिकापुर**

NAME CHANGE

I Prerana Tirkey D/O Anil Kumar Tirkey Age 18 Years Resident Of Domnara Colony, Post Farkanara, Teh-Kharsia, Distt Raigarh. 496665 Chhattisgarh. I Swear That My Name Is Prerana Tirkey. In Which My Name Has Been Recorded Prerna Tirkey In My Marksheet. And My Recorded Date Of Birth In Marksheet Is 29-10-2007. Whereas My Correct Date Of Birth Is 29-09-2007 And My Correct Name Is Prerana Tirkey Which Is Correct.
I Want To Get My Real Name Prerana Tirkey And Date Of Birth 29-09-2007 Registered In The Marksheet, My Correct Name Is Prerana Tirkey And Correct Date Of Birth Is 29-09-2007 In Aadhar Card. (Aadhar No- 4226 6941 0824) I Am Presenting An Affidavit To You To Get It Registered.

DEPONENT
Prerana Tirkey

C M Y K

बड़े सवाल

क्या मिलावट के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा है ? | क्या विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही है ? | क्या ऊपर तक पहुंच रही है सही जानकारी या हो रही है बंद आंखें ?

छत्तीसगढ़ को चाहिए ऐसा नेतृत्व, जो थाली और दवा को करे सुरक्षित !

महाराष्ट्र में तुकाराम मुंढे,छत्तीसगढ़ में कौन ?

खाद्य सुरक्षा के नाम पर आखिर किसका चल रहा राज ?

मिठाई में मिलावट खोजनी थी, विभाग कुर्सियों की मिठास में उलझ गया खाद्य एवं औषधि प्रशासन!

जनता की थाली में मिलावट,विभाग की फाइलों में 'सब ठीक'...कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का तुकाराम मुंढे

खाद्य सुरक्षा विभाग में 'सेफ' कौन? जनता की थाली या अधिकारियों की कुर्सियां?

मिलावटखोर बेखौफ,विभाग में कुर्सियों का खेल,छत्तीसगढ़ को अब तुकाराम मुंढे का इंतजार...

छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा तुकाराम मुंढे? खाद्य एवं औषधि प्रशासन में जनता की थाली से ज्यादा कुर्सियों की चिंता!

जनता की थाली असुरक्षित,विभाग में कुर्सियों की सुरक्षा पक्की! खाद्य एवं औषधि प्रशासन पर व्यंग्यात्मक सवाल

कौन देखेगा जनता की थाली? खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कार्रवाई से ज्यादा तबादले-पदोन्नति की चर्चा

खाद्य सुरक्षा की कुर्सी पर कौन? छत्तीसगढ़ में तुकाराम मुंढे की जरूरत या व्यवस्था सुधारने की?

जनता की थाली में मिलावट,विभाग की फाइलों में 'सब ठीक'...कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का तुकाराम मुंढे?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मौजूदा आधिकारिक जानकारी में तुकाराम मुंढे को आयुक्त बताया गया है,और विभाग अपने मूल उद्देश्य को खाद्य पदार्थों,दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा,गुणवत्ता तथा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना बताता है,यही वह बिंदु है जहां से छत्तीसगढ़ के लिए एक असहज लेकिन जरूरी सवाल निकलता है कि आखिर यहां कौन बनेगा तुकाराम मुंढे?

यह सवाल किसी अधिकारी को महान और किसी को निकम्मा घोषित करने के लिए नहीं है, सवाल व्यवस्था का है,खाद्य एवं औषधि प्रशासन का नाम सुनते ही आम आदमी की उम्मीद बहुत सीधी होती है की उसकी थाली में सुरक्षित भोजन पहुंचे,दूध-मिठाई-मसाले में मिलावट न हो,दवा मानक के अनुरूप हो और नकली या अमानक उत्पाद बाजार में टिक न पाए,महाराष्ट्र एफडीए की आधिकारिक जानकारी भी निरीक्षण, निगरानी और अमानक, मिलावटी,नकली या प्रतिबंधित खाद्य एवं दवा उत्पादों के विरुद्ध कार्रवाई को अपनी मूल भूमिका का हिस्सा बताती है,लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से विभाग की चर्चा का बड़ा हिस्सा यदि तबादला,पदस्थापना, अतिरिक्त प्रभार,पदोन्नति और कथित वसूली के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमने लगे,तो फिर जनता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि उसकी थाली और उसकी दवा की सुरक्षा का नंबर आखिर कब आएगा?

विभाग का असली काम कहीं फाइलों के नीचे तो नहीं दब गया?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां केवल फाइलों का वजन देखकर काम की सफलता मापी जाए,यहां असली परीक्षा बाजार में होती है,मिठाई की दुकान पर,होटल की रसोई में,दूध के कारोबार में,खाद्य निर्माण इकाई में,दवा दुकान में और उस प्रयोगशाला में जहां नमूनों की जांच होती है,आधिकारिक नियामकीय ढांचे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है और वह खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा मैदानी अधिकारी होता है,नामित अधिकारी को निरीक्षण,नमूने,शिकायतों और आगे की कार्रवाई की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं,यानी व्यवस्था का मकसद साफ है की कानून कागज पर नहीं,बाजार में दिखाई दे,अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितने निरीक्षण नियमित होते हैं? कितने नमूने लिए जाते हैं? कितने नमूने फेल होते हैं? फेल नमूनों पर कितने मामलों में अभियोजन या दंड होता है? कितने बड़े होटल और खाद्य निर्माता उसी कठोरता से जांचे जाते हैं जिस कठोरता से छोटा दुकानदार जांचा जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण...क्या कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से इतना पारदर्शी है कि आम आदमी खुद देख सके कि विभाग ने क्या किया? अगर जवाब आंकड़ों में है तो आंकड़े सामने आने चाहिए,क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति विभाग की उपलब्धि बता सकती है,लेकिन आंकड़े विभाग की असली परीक्षा बताते हैं।

त्योहार आया,अभियान आया, त्योहार गया,क्या निगरानी भी गई?-मिलावट के खिलाफ अभियान जरूरी हैं,त्योहारों के समय मिठाई और खाद्य पदार्थों की जांच भी जरूरी है, लेकिन व्यंग्य यहीं से शुरू होता है की अगर मिलावट सिर्फ त्योहारों में पैदा होती है तो अभियान पर्याप्त है,लेकिन यदि मिलावट सालभर चलती है तो फिर विभाग की निगरानी भी सालभर चलनी चाहिए,एक दिन में कुछ दुकानों से नमूने लेना और उसे पूरे जिले की खाद्य सुरक्षा का प्रमाण-पत्र मान लेना आसान है,कठिन काम है लगातार निगरानी,वैज्ञानिक नमूना संग्रह,प्रयोगशाला परीक्षण,समयबद्ध कार्रवाई और दोषी पर समान कानून लागू करना,महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत,प्रवर्तन और विभागीय संपर्क व्यवस्था भी प्रकाशित है, छत्तीसगढ़ में भी यदि ऐसी पारदर्शिता बढ़े तो सवाल कम और भरोसा ज्यादा होगा।

सबसे गंभीर आरोप...कार्रवाई या कथित 'रेट'? छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लेकर सार्वजनिक चर्चा में कथित वसूली और कार्रवाई के नाम पर लेन-देन के आरोप भी सामने आते रहे हैं,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के बिना उन्हें तथ्य नहीं कहा जा सकता,लेकिन आरोप बार-बार सामने आएं तो उन्हें जांच के बिना दफन कर देना भी स्वस्थ प्रशासन नहीं है,निष्पक्ष रास्ता एक ही है...जांच करिए,आरोप गलत है तो अधिकारी को क्लीन चिट दीजिए,सही है तो दोषी पर कार्रवाई कीजिए,लेकिन चुप्पी को जवाब मान लेना सबसे खराब विकल्प है,क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कुर्सी का काम 'रेट तय करना' नहीं,मानक तय कराना है,यदि व्यापारी नियम तोड़ता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो, यदि वह नियमों का पालन करता है तो उसे बेवजह परेशान न किया जाए,यही नियामक की विश्वसनीयता है।

विजय चौधरी,दीपक अग्रवाल,राजेंद्र कटारा या अमित कटारिया...कसौटी नाम नहीं,काम होना चाहिए...विभाग से जुड़े विमर्श में दीपक अग्रवाल,राजेंद्र कटारा,अमित कटारिया और विजय चौधरी जैसे नामों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं,लेकिन किसी अधिकारी को केवल आरोपों के आधार पर ईमानदार या भ्रष्ट घोषित करना पत्रकारिता नहीं होगी,असली कसौटी उनका रिकॉर्ड है, कितने निरीक्षण? कितने नमूने? कितने फेल? कितने अभियोजन? कितनी अंतिम कार्रवाई? कितनी शिकायतों का निस्तारण? कितने अधिकारियों पर कार्रवाई? कितने बड़े कारोबारी कानून के दायरे में आए? यही रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, यदि यह रिकॉर्ड अच्छा है तो विभाग को किसी 'मुंढे' की जरूरत नहीं,और यदि रिकॉर्ड कमजोर है तो केवल पदनाम बदलने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा।

अमित कटारिया तक सही जानकारी पहुंच रही है या सिर्फ सुंदर फाइलें?-किसी भी आयुक्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि नीचे से ऊपर आने वाली सूचना कितनी सही है,आयुक्त हर दुकान पर खुद नहीं जा सकता, वह अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्णय लेता है,इसलिए सवाल केवल आयुक्त की नीयत का नहीं,सूचना तंत्र की विश्वसनीयता का भी है,अगर नीचे सब ठीक है तो शिकायतों का निस्तारण तेजी से होना चाहिए,अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि शिकायत झूठी है तो शिकायतकर्ता को कारण सहित जवाब मिलना चाहिए,वरना ऊपर बैठे अधिकारी को फाइल में प्रदेश बिल्कुल चमकदार दिख सकता है और जमीन पर जनता कुछ और देख सकती है,प्रशासन में इसे ही शायद 'फाइल की हरी तस्वीर और बाजार की काली सच्चाई' कहा जा सकता है।

छोटे दुकानदार पर डंडा,बड़े पर सन्नाटा तो सवाल उठेंगे...

एक पुराना सवाल फिर सामने आता है की क्या विभाग की कार्रवाई सब पर समान है? छोटे दुकानदार की दुकान में जांच आसान है,लेकिन बड़े होटल,बड़े खाद्य निर्माता,प्रभावशाली कारोबारी और बड़े प्रतिष्ठान भी क्या उसी नियमितता से जांचे जाते हैं? यदि विभाग कहता है कि हां, तो जिलेवार और श्रेणीवार आंकड़े सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए,कितने निरीक्षण हुए, कितने नमूने लिए गए और कितने मामलों में कार्रवाई हुई...यह सामने आते ही चर्चा आरोप से तथ्य पर आ जाएगी,कानून की असली ताकत तब दिखाई देती है जब उसका वजन दुकान के आकार से नहीं,उल्लंघन की गंभीरता से तय होता है।

सुर्खियों में विभाग का मूल काम कम,कुर्सियों की चर्चा ज्यादा क्यों?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लेकर हालिया बहसों में पदोन्नति, पदस्थापना, अतिरिक्त प्रभार और स्थापना शाखा के निर्णयों पर सवाल उठे हैं,नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर 13 कर्मचारियों की पदोन्नति और इसी वर्ष नमूना सहायक के 30 पदों की भर्ती का विज्ञापन भी इसी व्यापक चर्चा का हिस्सा बना है, इन निर्णयों को सही या गलत बताने के लिए लागू सेवा नियम,पदोन्नति कोटा, पात्रता,डीपीसी की कार्यवाही और स्वीकृत पदों की वास्तविक स्थिति देखना जरूरी है, लेकिन एक सवाल तो बनता ही है—विभाग की दीर्घकालिक मानव संसाधन नीति आखिर है क्या? अगर तकनीकी पदों की कमी है तो सीधी भर्ती कब होगी? अगर पदोन्नति से पद भरने हैं तो उसका स्पष्ट कोटा क्या है? अगर दोनों रास्ते हैं तो दोनों का अनुपात कितना है? और यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से तकनीकी पद पर पहुंच रहा है तो उसकी योग्यता और अनुभव का परीक्षण किस स्तर पर हुआ?

क्या नितेश मिश्रा जैसे अधिकारी पर भरोसा करे छत्तीसगढ़?-खाद्य एवं औषधि प्रशासन में अधिकारी की कुर्सी सिर्फ सरकारी कुर्सी नहीं,जनता की थाली और दवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ऐसे में जब किसी अधिकारी की लंबे समय तक एक ही संभाग में पदस्थापना,कई जिलों के अतिरिक्त प्रभार और महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठें,तो जनता का सवाल भी स्वाभाविक है–भरोसा किस आधार पर किया जाए? नितेश कुमार मिश्रा का पक्ष है कि उनकी पदस्थापनाएं शासन के आदेश से हुई और वर्तमान में भी कई अधिकारी एक से अधिक जिलों का दायित्व संभाल रहे हैं, यह पक्ष अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यंग्य यहीं है...अगर सब कुछ शासन के आदेश से हुआ,तो फिर आदेशों की पूरी फाइल सार्वजनिक कर दीजिए,जनता भी देख ले कि यह प्रशासनिक दक्षता थी या विभागीय व्यवस्था का कोई खास 'फॉर्मूला',दस वर्षों तक एक ही संभाग के आसपास मूल और अतिरिक्त प्रभारों का सिलसिला,फिर पदोन्नति के बाद गृह क्षेत्र के आसपास जिम्मेदारी–इसे संयोग कहा जाए,योग्यता कहा जाए या फिर सरकारी सेवा का ऐसा भाग्य जिसे हर अधिकारी हासिल करना चाहे? सवाल यह भी है कि एक अधिकारी को बार-बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के पीछे विभागीय कसौटी क्या थी। क्या उपलब्धियां थीं? क्या निरीक्षण और कार्रवाई का रिकॉर्ड था? कितने नमूने लिए गए,कितने अमानक पाए गए और कितनों पर प्रभावी कार्रवाई हुई? क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की असली परीक्षा यह नहीं कि वह कितनी कुर्सियां संभाल सकता है,बल्कि यह है कि वह जनता की थाली कितनी सुरक्षित रख सकता है,और आखिर में सबसे सीधा सवाल क्या छत्तीसगढ़ को ऐसे अधिकारी पर आंख मूंदकर भरोसा करना चाहिए,या सरकार को पहले उनके पूरे कार्यकाल,पदस्थापनाओं,अतिरिक्त प्रभारों और विभागीय निर्णयों का स्वतंत्र एवं पारदर्शी ऑडिट कराकर जनता को बताना चाहिए कि 'होनहार अधिकारी' की सरकारी परिभाषा आखिर है क्या?

रिपोर्ट कार्ड चाहिए...

तुकाराम मुंढे का नाम यहां किसी चमत्कारिक समाधान की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी भी अधिकारी का मूल्यांकन काम से होना चाहिए,महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट स्वयं सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवाएं,सुरक्षित महाराष्ट्र को मिशन के रूप में प्रस्तुत करती है और खाद्य-दवा सुरक्षा को विभाग का केंद्रीय उद्देश्य बताती है, छत्तीसगढ़ को भी यही चाहिए...सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवाएं,सुरक्षित छत्तीसगढ़,लेकिन इसके लिए पहले यह देखना होगा कि विभाग का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है,पिछले एक वर्ष में जिलेवार कितने नमूने लिए गए? कितने फेल हुए? फेल नमूनों पर क्या कार्रवाई हुई? कितने मामले न्यायालय तक पहुंचे? कितने मामलों में दंड हुआ? कितनी शिकायतें आईं और कितनी का निस्तारण हुआ? अगर इन सवालों के जवाब साफ हैं तो फिर तुकाराम मुंढे की तलाश की जरूरत नहीं,छत्तीसगढ़ का कोई भी अधिकारी अपने काम से खुद उदाहरण बन सकता है।

व्यंग्य का आखिरी सवाल...मिठाई कौन देखेगा,कुर्सी कौन?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन में अगर सब कुछ नियम से चल रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं,फाइल खोलिए,नियम दिखाइए,डीपीसी की नोटशीट बताइए,निरीक्षण के आंकड़े रखिए और सवाल खत्म कीजिए,लेकिन यदि जनता की थाली की सुरक्षा वाली कुर्सी पर बैठकर सबसे ज्यादा चर्चा उसी कुर्सी की हो रही है,तो सवाल उठेंगे ही,महाराष्ट्र में तुकाराम मुंढे हैं पर छत्तीसगढ़ में कौन होगा? कौन ऐसा अधिकारी होगा जो मिठाई की दुकान पर सिर्फ मिठाई नहीं, मिलावट भी देखेगा? कौन ऐसा होगा जो दवा की दुकान पर सिर्फ लाइसेंस नहीं,दवा की गुणवत्ता भी देखेगा? कौन ऐसा होगा जो छोटे दुकानदार से नियम पूछते समय बड़े कारोबारी से भी वही सवाल पूछेगा? कौन ऐसा होगा जो अधीनस्थ की सुंदर रिपोर्ट देखकर संतुष्ट होने के बजाय कभी-कभी बाजार की सच्चाई भी देखेगा? क्योंकि अंततः खाद्य एवं औषधि प्रशासन की असली कुर्सी रायपुर के कार्यालय में नहीं,जनता की थाली और मरीज की दवा में है,और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा व्यंग्य है की जिस विभाग को जनता के खाने और दवा की शुद्धता देखनी है,उसकी अपनी व्यवस्था कितनी शुद्ध है, इसका टेस्ट भी अब जनता ही ले रही है।

नमक की बोरियों के नीचे छिपाया 1.54 करोड़ का गांजा...ओडिशा से सुकमा के रास्ते राजस्थान ले जा रहे थे,2 गिरफ्तार

सुकमा,18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने 308 किलो 280 ग्राम गांजा पकड़ा है। गांजा पिकअप में नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 54 लाख 14 हजार रुपए बताई गई है। इसके साथ ही, पुलिस ने पिकअप वाहन समेत कुल 1 करोड़ 64 लाख 49 हजार 550 रुपए की संपत्ति जब्त की है। राजस्थान के 2 आरोपी शिव कुमार प्रजापति (24) और उदय राम बलई (24) को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोंटा थाना इलाके का है।

ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे थे गांजा : एएसपी रोहित शाह ने बताया कि, 18 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी। बताया गया कि पिकअप वाहन क्रमांक RJ-27-GE-6757 में ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र से गांजा लेकर कोंटा के रास्ते राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद कोंटा पुलिस ने कोंटा-मोटू मुख्य मार्ग स्थित कृष्ण मंदिर चौक, वार्ड क्रमांक 5 डोंडरा के पास नाकेबंदी की। सुबह करीब 6:10 बजे संदिग्ध पिकअप को रोककर उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया।

नमक की बोरियों के नीचे मिले गांजे के पैकेट : पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो ऊपर से नमक की बोरियां रखी मिलीं। इनके नीचे गांजे के पैकेट छिपाकर रखे गए थे। वजन करने पर कुल 308 किलो 280 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से शिव कुमार प्रजापति और उदय राम बलई को गिरफ्तार किया है। दोनों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गाडरमाल के रहने वाले हैं।

1.64 करोड़ की संपत्ति जब्त : पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत करीब 1.54 करोड़ रुपए है। वहीं पिकअप वाहन समेत जब्त संपत्ति की कुल कीमत 1 करोड़ 64 लाख 49 हजार 550 रुपए आंकी गई है। कोंटा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)